बहुजन हिताय! बहुजन सुखाय!

सक्षम भारत

राष्ट्रीय हिन्दी दैनिक | इन्द्रजीत सिंह, मुख्य संवाददाता/सचिव, CNSI-Delhi

दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, उत्तर प्रदेश से प्रसारित

www.sakshambharat;net, E-mail : saksham.bharat@hotmail.com

Member : CENTRAL NEWSPAPER SOCIETY OF INDIA DELHI

● वर्ष: 24 ● अंक: 247 ● नई दिल्ली ● सोमवार 20 जुलाई 2026 ● प्रभात कालीन ● मूल्य: 3 रूपया ● पृष्ठ: 4

रिपब्लिकन मजदूर संगठन के सदस्य बनें

E-mail : rmsdp@hotmail.com

अनागारिक गीता भारती भवन

बी-2/370, सुल्तानपुरी

दिल्ली-86

सेंट जेवियर्स हाई स्कूल के तीन विद्यार्थियों ने नीट किया क्वालीफाई, भाई-बहन की सफलता बनी प्रेरणा

पडरौना, कुशीनगर। सेंट जेवियर्स हाई स्कूल, पडरौना के तीन विद्यार्थियों ने राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा उत्तीर्ण कर विद्यालय एवं जनपद का नाम रोशन किया है। सफलता प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों में सक्षम, सबाहत और नचिकेता शामिल हैं। इनमें सक्षम और उनकी बहन सबाहत विकासखंड पडरौना के प्रधान पट्टी गांव के निवासी हैं। दोनों भाई-बहन ने दूसरे प्रयास (सेकंड अटेम्प्ट) में नीट परीक्षा सफलतापूर्वक उत्तीर्ण कर अपने परिवार और क्षेत्र का गौरव बढ़ाया है। इनके पिता पंचायत मित्र के पद पर कार्यरत हैं। दोनों की सफलता ने यह संदेश दिया है कि दृढ़ संकल्प और निरंतर मेहनत से सफलता अवश्य प्राप्त होती है।

राम मंदिर चंदे की चोरी पर राहुल-खड़गे ने पीएम मोदी को लिखा पत्र, कहा- आपकी चुप्पी मंजूर नहीं

नई दिल्ली। अयोध्या राम मंदिर में दान की कथित चोरी को लेकर मचे विवाद के बीच, कांग्रेस नेता राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे ने रविवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखकर श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के वित्तीय मामलों की जांच की मांग की। उन्होंने कहा कि अपनी मेहनत की कमाई आस्था के साथ दान करने वाले लाखों श्रद्धालु चोरी से ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं। संसद के दोनों सदनों में विपक्ष के नेताओं ने अपने पत्र में कहा कि आप श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट में हजारों करोड़ रुपये की चोरी के बारे में जानते हैं। जिन लाखों श्रद्धालुओं ने आस्था, भक्ति और भरोसे के साथ अपनी मेहनत की कमाई दान की थी, वे इस चोरी से खुद को ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं। उन्होंने प्रधानमंत्री से कहा कि उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों पर संसद में ट्रस्ट बनाने की घोषणा की थी, लेकिन इसके सदस्य पूरी तरह से उनकी सरकार ने ही नियुक्त किए थे। उन्होंने कहा कि आपने भारत के सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों पर संसद में ट्रस्ट बनाने की घोषणा की थी, लेकिन इसके सदस्य पूरी तरह से आपकी सरकार ने ही नियुक्त किए हैं। यह बात सबको पता है कि ट्रस्ट के सदस्य RSS, VHP और उनसे जुड़े संगठनों से जुड़े हुए हैं। इसके बदनाम पूर्व जनरल सेक्रेटरी भी आपके करीबी सहयोगी थे। कांग्रेस नेताओं ने कहा कि इस मुद्दे पर प्रधानमंत्री की चुप्पी स्वीकार्य नहीं है और उनसे जवाबदेही तय करने और भरपाई सुनिश्चित करने की मांग की। कांग्रेस नेताओं ने कहा कि ऐसे अपराध के मामले में आपकी चुप्पी मंजूर नहीं है। जवाबदेही तय करना और नुकसान की भरपाई सुनिश्चित करना आपकी जिम्मेदारी है। हम आपसे आग्रह करते हैं कि आप ट्रस्ट के वित्तीय मामलों की तुरंत एक स्वतंत्र और व्यापक जांच का आदेश दें, जिसमें नकद, सोना और चांदी समेत सभी चढ़ावों के प्रबंधन की जांच भी शामिल हो। उन्होंने यह भी मांग की कि जांच के नतीजे और ट्रस्ट के हिसाब-किताब को सार्वजनिक किया जाए ताकि हर भक्त को पता चल सके कि उनके चढ़ावे का इस्तेमाल कैसे किया गया है। कांग्रेस नेताओं ने कहा कि जो भी लोग इसके लिए जिम्मेदार पाए जाएं, उन्हें जवाबदेह ठहराया जाना चाहिए, चाहे उनका पद या प्रभाव कुछ भी हो। आपकी सरकार और ट्रस्ट की विश्वसनीयता इस बात पर निर्भर करती है कि आप कितनी पारदर्शिता और तेजी से कार्रवाई करते हैं। भारत की जनता सब देख रही है। जय हिंद! पत्र में लिखा है कि जांच के नतीजे और ट्रस्ट के हिसाब-किताब को सार्वजनिक किया जाना चाहिए ताकि हर भक्त को पता चल सके कि उनके चढ़ावे का इस्तेमाल कैसे किया गया है।

एबीवीपी में अध्यक्ष पद के लिए महिला ब्राह्मण चेहरे पर मंथन, सोशल इंजीनियरिंग साधने की तैयारी

नई दिल्ली। दिल्ली विश्वविद्यालय छात्रसंघ (डूसू) चुनाव को लेकर अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद (एबीवीपी) ने अंदरूनी स्तर पर तैयारियां तेज कर दी हैं। संगठन के भीतर इस बार अध्यक्ष पद के लिए सबसे अधिक चर्चा महिला उम्मीदवार को मैदान में उतारने को लेकर है। सूत्रों के अनुसार, संगठन सामाजिक और चुनावी समीकरणों को साधने के लिए महिला ब्राह्मण छात्रा को अध्यक्ष पद का टिकट देने के विकल्प पर गंभीरता से विचार कर रहा है। हालांकि अंतिम फैसला केंद्रीय नेतृत्व और संगठन की चुनाव समिति की सहमति के बाद ही लिया जाएगा। सूत्रों के मुताबिक, अध्यक्ष पद के लिए इस बार 13 छात्र नेता सक्रिय रूप से दावेदारी कर रहे हैं। इनमें महिमा शर्मा, आयुषी शर्मा, रिया मलिक, यश डबास, ओजस्वी सहरावत, आलोक अत्री, हेमंत खोखर, नितिन तंवर, सनी डेढ़ा, तुषार बैसला, लक्ष्य राज सिंह, प्रणव पराशर, ईशु मौर्य के नाम प्रमुख हैं। संगठन के भीतर टिकट को लेकर लगातार बैठकों और फीडबैक का दौर चल रहा है। दावेदारों में बड़ी संख्या बौद्ध अध्ययन विभाग से जुड़े छात्रों की है, जबकि प्रणव पराशर, ईशु मौर्य, आशीष प्रताप सिंह और लक्ष्य राज सिंह विधि संकाय (लॉ फैकल्टी) से जुड़े हैं। वहीं रिया मलिक श्यामा प्रसाद मुखर्जी कालेज और आयुषी शर्मा लक्ष्मीबाई कालेज की छात्रा हैं। सूत्रों का कहना है कि महिला चेहरे पर विचार होने की स्थिति में आयुषी शर्मा और रिया मलिक जैसे नामों की भी चर्चा संगठन के भीतर हो रही है, हालांकि किसी नाम पर अभी अंतिम निर्णय नहीं हुआ है। एबीवीपी सूत्रों का कहना है कि इस बार डूसू चुनाव में महिला नेतृत्व को आगे लाने से छात्राओं के बीच संगठन की स्वीकार्यता और मजबूत हो सकती है। साथ ही, जातीय और क्षेत्रीय संतुलन को ध्यान में रखते हुए ब्राह्मण समाज से आने वाले महिला चेहरे पर दांव लगाने का विकल्प भी संगठन के सामने है। टिकट चयन में संगठनात्मक सक्रियता, छात्र आंदोलनों में भूमिका, कालेज और विभाग में प्रभाव, सार्वजनिक छवि और जीत की संभावना को प्रमुख आधार बनाया जा रहा है। डूसू चुनाव दिल्ली विश्वविद्यालय की छात्र राजनीति का सबसे बड़ा चुनाव माना जाता है। अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सचिव और संयुक्त सचिव के चार केंद्रीय पदों के लिए होने वाला यह चुनाव राष्ट्रीय राजनीति की दृष्टि से भी महत्वपूर्ण माना जाता है। कई राष्ट्रीय नेता अपने छात्र राजनीतिक जीवन की शुरुआत डूसू से कर चुके हैं। पिछले वर्ष डूसू चुनाव में एबीवीपी ने चार में से तीन केंद्रीय पदों पर जीत दर्ज की थी। अध्यक्ष पद पर एबीवीपी के आर्यन मान विजयी हुए थे, जबकि सचिव और संयुक्त सचिव के पद भी परिषद के खाते में गए थे। उपाध्यक्ष पद पर एनएसयूआइ ने जीत हासिल की थी।

जंतर-मंतर कार्यक्रम को लेकर पुलिस में शिकायत, कुणाल कामरा और प्रकाश राज के खिलाफ केस दर्ज करने की मांग

नई दिल्ली।

नई दिल्ली में जंतर-मंतर पर राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा (नीट) के मुद्दे पर चल रहे छात्र आंदोलन के दौरान कथित तौर पर हिंदू देवी-देवताओं के अपमान और भड़काऊ भाषण दिए जाने का आरोप लगाते हुए सर्वोच्च न्यायालय के अधिवक्ताओं और हिंदू जनजागृति समिति के प्रतिनिधियों ने संसद मार्ग थाना में शिकायत दी है। प्रतिनिधिमंडल ने संबंधित लोगों के खिलाफ मामला दर्ज करने और जांच कराने की मांग की है। शिकायत में कहा गया है कि आंदोलन के मंच से कुछ ऐसे वक्तव्य और प्रस्तुतियां दी गईं, जिनसे हिंदू समाज की धार्मिक भावनाएं आहत हुई हैं। शिकायतकर्ताओं ने आरोप लगाया कि हास्य कलाकार कुणाल कामरा ने भगवान राम को लेकर आपत्तिजनक टिप्पणी की। साथ ही एक महिला द्वारा गाए गए गीत को भी धार्मिक भावनाएं भड़काने वाला बताया गया है। प्रतिनिधिमंडल ने अभिनेता प्रकाश राज पर भी मंच से कथित रूप से युवाओं को व्यवस्था के खिलाफ भड़काने और विवादित टिप्पणियां करने का आरोप लगाया है। शिकायत में यह भी कहा गया है कि कार्यक्रम में प्रतिबंधित संगठन से जुड़े होने का आरोप झेल चुके एक व्यक्ति की मौजूदगी की भी जांच होनी चाहिए। शिकायत देने वालों में अधिवक्ता मकरंद डी. अडकर, अमिता सचदेवा, मयंक द्विवेदी, अतुल शर्मा, पार्थ यादव, यादवेंद्र सक्सेना, केशरी सत्या तथा हिंदू जनजागृति समिति के प्रतिनिधि कार्तिक सालुंखे और श्रीराम लुकतुके शामिल थे।

प्रतिनिधिमंडल ने पुलिस से उच्चतम न्यायालय के घृणा फैलाने वाले भाषणों से जुड़े फैसले का हवाला देते हुए स्वतः संज्ञान लेकर कार्रवाई करने की मांग की है। शिकायतकर्ताओं ने भारतीय न्याय संहिता की विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज करने तथा पूरे प्रकरण की गहन जांच कराने की अपील की है। साथ ही उन्होंने केंद्रीय गृह मंत्री और दिल्ली पुलिस आयुक्त से आंदोलन के वित्तपोषण और अन्य पहलुओं की भी जांच कराने का अनुरोध किया है।

राष्ट्रपति मुर्मू का मिशन यूरोप- 3 देशों के दौरे पर रवाना, 30 साल बाद रोमानिया से सुधरेंगे रिश्ते

नई दिल्ली। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू व्यापार, प्रौद्योगिकी एवं अन्य प्रमुख क्षेत्रों में सहयोग को बढ़ावा देने तथा लोगों के बीच आपसी संबंध को मजबूत करने के उद्देश्य से रविवार को मोल्दोवा, उत्तर मैसेडोनिया और रोमानिया की यात्रा पर रवाना हो गईं। मुर्मू की यात्रा का पहला चरण सोमवार से मोल्दोवा में शुरू होगा। यह किसी भी भारतीय राष्ट्रपति की मोल्दोवा की पहली यात्रा होगी। मुर्मू मोल्दोवा की राष्ट्रपति मैया सैंडू के साथ द्विपक्षीय और प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता करेंगी। इसके अलावा वह मोल्दोवा की संसद के अध्यक्ष इगोर ग्रोसु से भी मुलाकात करेंगी। राष्ट्रपति का मोल्दोवा-भारत संसदीय मैत्री समूह के सदस्यों के साथ संवाद, भारत-मोल्दोवा व्यापार मंच को संबोधित करने और वहां रह रहे भारतीय समुदाय के सदस्यों से मुलाकात का भी कार्यक्रम है। विदेश मंत्रालय ने शुक्रवार को जारी बयान में कहा, भारत और मोल्दोवा के बीच मैत्रीपूर्ण संबंध हैं। राष्ट्रपति की यह यात्रा महत्वपूर्ण साबित होगी तथा

द्विपक्षीय संबंधों को व्यापक साझेदारी के नए स्तर पर ले जाएगी। बयान में कहा गया कि कृषि, स्वास्थ्य सेवा, औषधि उद्योग, सूचना प्रौद्योगिकी और शिक्षा जैसे क्षेत्रों में दोनों देशों के बीच पारस्परिक रूप से लाभकारी सहयोग की व्यापक संभावनाएं हैं। राष्ट्रपति मुर्मू 21 से 22 जुलाई तक उत्तर मैसेडोनिया की भी यात्रा करेंगी। राष्ट्रपति गोर्डाना सिलजानोव्स्का-दावकोवा के निमंत्रण पर होने वाली यह यात्रा भी किसी भारतीय राष्ट्रपति की इस देश की पहली यात्रा होगी। उत्तर मैसेडोनिया में राष्ट्रपति मुर्मू अपनी समकक्ष राष्ट्रपति सिलजानोवस्का-दवाकोवा के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगी। इसके अलावा वह प्रधानमंत्री ह्रिस्टिजन मिकोस्की, संसद के अध्यक्ष से मुलाकात करेंगी तथा उत्तर मैसेडोनिया की संसद को संबोधित भी करेंगी। राष्ट्रपति भारत-उत्तर मैसेडोनिया व्यापार मंच को भी संबोधित करेंगी। दोनों देश कृषि, औषधि उद्योग, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, सूचना प्रौद्योगिकी (आईटी) और आईटी-सक्षम सेवाओं (आईटीईएस) जैसे प्राथमिकता वाले क्षेत्रों में आर्थिक सहयोग को और मजबूत करना चाहते हैं। विदेश मंत्रालय के सचिव (पश्चिम) सिबी जॉर्ज ने शुक्रवार को कहा, तीन देशों की यह यात्रा मध्य और पूर्वी यूरोप के साथ भारत के बढ़ते जुड़ाव को प्रदर्शित करती है और इस क्षेत्र के देशों के साथ अपनी साझेदारी को मजबूत करने के हमारे संकल्प को फिर से दोहराती है। यह यूरोप के साथ भारत के व्यापक जुड़ाव और यूरोपीय संघ के साथ रणनीतिक साझेदारी को भी आगे बढ़ाती है। विदेश मंत्रालय के अनुसार, रोमानिया के राष्ट्रपति निकुसोर डैन के निमंत्रण पर मुर्मू 23 से 25 जुलाई तक इस देश की यात्रा करेंगी। तीन दशक से भी अधिक समय के बाद किसी भारतीय राष्ट्रपति का इस दक्षिण-पूर्वी यूरोपीय देश का पहला दौरा होगा। राष्ट्रपति मुर्मू भारत-रोमानिया बिजनेस फोरम को भी संबोधित करेंगी और प्रवासी भारतीयों से बातचीत करेंगी। विदेश मंत्रालय ने कहा, रोमानिया यूरोपीय संघ में एक अहम साझेदार है और भारत-यूरोपीय संघ मुक्त व्यापार समझौते के पूरा होने से आगामी वर्षों में दोनों देशों के बीच आर्थिक साझेदारी और मजबूत होगी। मंत्रालय के अनुसार, मुर्मू का इन तीन देशों का दौरा यह प्रदर्शित करता है कि भारत इन देशों के साथ अपने द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करने और इस क्षेत्र के साथ संबंधों को कितना महत्व देता है। मोल्दोवा, उत्तर मैसेडोनिया और रोमानिया ने पिछले साल जम्मू-कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकवादी हमले की निंदा की थी और आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में भारत को अपना पूर्ण समर्थन व्यक्त किया था।

दिल्ली में सिक्योरिटी टाइट... ट्रैफिक एडवाइजरी जारी, मॉनसून सत्र को लेकर पुलिस की तैयारी; लोगों से की गई ये अपील

नई दिल्ली ।

20 जुलाई 2026 से शुरू हो रहे संसद के मॉनसून सत्र को देखते हुए दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने राजधानी के लोगों के लिए विस्तृत ट्रैफिक एडवाइजरी जारी की है. संसद सत्र के दौरान लोकसभा और राज्यसभा की कार्यवाही चलने के कारण नई दिल्ली में सुरक्षा-व्यवस्था पहले से अधिक कड़ी रहेगी. इसके चलते वीआईपी और वीवीआईपी मूवमेंट भी बढ़ेगा, जिससे संसद भवन और आसपास के इलाकों में ट्रैफिक का दबाव सामान्य दिनों की तुलना में काफी अधिक रहने की संभावना है. ऐसे में लोगों से अपील की गई है कि वे अपनी यात्रा की पहले से योजना बनाएं और जहां तक संभव हो, इन मार्गों से बचें ताकि अनावश्यक जाम में फंसने से बचा जा सके. दिल्ली ट्रैफिक पुलिस के मुताबिक, संसद सत्र के दौरान रफी मार्ग, मोतीलाल नेहरू मार्ग, मौलाना आजाद रोड, के. कामराज मार्ग, रायसीना रोड, राजेंद्र प्रसाद रोड, पार्लियामेंट स्ट्रीट, अशोका रोड, तालकटोरा रोड, पंडित पंत मार्ग और रकाबगंज गुरुद्वारा रोड पर ट्रैफिक का दबाव सबसे अधिक रहेगा. इन सड़कों पर समय-समय पर सुरक्षा कारणों से ट्रैफिक को रोका जा सकता है या डायवर्ट किया जा सकता है. ऐसे में इन मार्गों का उपयोग केवल बेहद जरूरी होने पर ही करने की सलाह दी गई है.

कई चौराहों पर प्रभावित रहेगा ट्रैफिक

इसके अलावा कई महत्वपूर्ण चौराहों और राउंडअबाउट पर भी ट्रैफिक प्रभावित रहेगा. इनमें विजय चौक, बोट क्लब, रेल भवन राउंडअबाउट, सुनहरी मस्जिद राउंडअबाउट, पटेल चौक राउंडअबाउट, बूटा सिंह राउंडअबाउट, प्राइम चौक राउंडअबाउट, जीआरजी राउंडअबाउट और जलेबी चौक राउंडअबाउट शामिल हैं. इन इलाकों में सुरक्षा जांच, वीआईपी काफिलों की आवाजाही और ट्रैफिक डायवर्जन के कारण वाहनों की रफ्तार धीमी रह सकती है. दफ्तर जाने वाले लोगों और रोजाना इन रास्तों का इस्तेमाल करने वालों को अतिरिक्त समय लेकर निकलने की सलाह दी गई है.

ट्रैफिक पुलिस ने सुझाए वैकल्पिक मार्ग

ट्रैफिक पुलिस ने लोगों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए कई वैकल्पिक मार्ग भी सुझाए हैं. यदि संभव हो तो लोग जनपथ, मान सिंह रोड, अकबर रोड, तीन मूर्ति मार्ग, शांति पथ, मौलाना अब्दुल कलाम आजाद रोड, कमाल अतातुर्क मार्ग, पंचशील मार्ग, विनय मार्ग, कनॉट प्लेस का आउटर सर्किल, बाबा खड़क सिंह मार्ग, आरएमएल राउंडअबाउट, मदर टेरेसा क्रेसेंट रोड, 11 मूर्ति और सरदार पटेल मार्ग का उपयोग कर सकते हैं. इन मार्गों पर ट्रैफिक का दबाव अपेक्षाकृत कम रहने की संभावना है और इससे लोगों को अपने गंतव्य तक पहुंचने में सुविधा होगी.

किसी भी समय ट्रैफिक व्यवस्था में किया जा सकता है बदलाव

दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने कहा है कि मानसून सत्र के दौरान सुरक्षा सर्वोच्च प्राथमिकता रहेगी. इसलिए हालात के अनुसार किसी भी समय ट्रैफिक व्यवस्था में बदलाव किया जा सकता है. जरूरत पड़ने पर कुछ मार्गों पर अस्थायी रूप से ट्रैफिक रोका जा सकता है या डायवर्ट किया जा सकता है. ऐसे में वाहन चालकों से अनुरोध है कि वे पुलिसकर्मियों के निर्देशों का पालन करें और जल्दबाजी या गलत दिशा में वाहन चलाने से बचें.

पुलिस ने यह भी सलाह दी है कि जो लोग नई दिल्ली, सेंट्रल दिल्ली या संसद भवन के आसपास के इलाकों में काम करते हैं, वे घर से निकलने से पहले ट्रैफिक की स्थिति जरूर देख लें. यदि संभव हो तो सार्वजनिक परिवहन या दिल्ली मेट्रो का इस्तेमाल करें, जिससे सड़क पर वाहनों की संख्या कम होगी और ट्रैफिक व्यवस्था सुचारु बनी रहेगी.

ट्रैफिक नियमों का पालन करने की अपील

दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने लोगों से धैर्य बनाए रखने और ट्रैफिक नियमों का पालन करने की अपील की है. साथ ही कहा गया है कि किसी भी प्रकार की ट्रैफिक संबंधी जानकारी, मार्ग परिवर्तन या सहायता के लिए लोग दिल्ली ट्रैफिक पुलिस की वेबसाइट और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर जारी अपडेट देखते रहें. इसके अलावा ट्रैफिक हेल्पलाइन 1095, 011-25844444 तथा व्हाट्सएप नंबर 8750871493 पर भी संपर्क किया जा सकता है. संसद के मानसून सत्र के दौरान सुरक्षा और यातायात व्यवस्था को सुचारु बनाए रखने के लिए बड़ी संख्या में दिल्ली ट्रैफिक पुलिस के जवान कई चौराहों और संवेदनशील स्थानों पर तैनात रहेंगे. इसलिए लोगों से सहयोग करने और निर्धारित ट्रैफिक डायवर्जन का पालन करने की अपील की गई है, ताकि सभी को सुरक्षित और सुगम यात्रा का अनुभव मिल सके.

सम्पादकीय...

संघ की रेटिंग?

आमतौर पर मुख्यमंत्रियों या मंत्रियों के कामकाज को आंकने के लिए संघ के पास अपना कोई घोषित मैकेनिज्म नहीं होता, पर सूत्रों की मानें तो भाजपा शासित राज्यों के मुख्यमंत्रियों के कामकाज को लेकर इन दिनों संघ भी किंचित उतना ही गंभीर है। शायद इसीलिए भी कि पिछले कुछ चुनावों से राज्यों में भगवा पताका लहराने में उसे भी ऐड़ी-चोटी का जोर लगाना पड़ा है। संघ ने भगवा मुख्यमंत्रियों के कामकाज को आंकने के लिए कई पैमाने तय किए थे, जिसमें उनके कार्यों की समीक्षा के अलावा, उनका संगठन से सामंजस्य, निजी इमेज की चिंता, ईमानदारी व कार्य की पारदर्शिता, संबंधित जाति में उनका असर, संघ को लेकर उनका विजन या भविष्य का रोड मैप, नौकरशाही से उनका तालमेल, जनता के साथ द्विपक्षीय संवाद आदि। सूत्रों की मानें तो इस सर्वे में हैरतअंगेज तरीके से देवेंद्र फडणवीस ने बाजी मार ली, छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय और यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की रेटिंग भी काफी अच्छी रही। ओडिशा के भगवा सीएम माझी को जहां औसत रेटिंग दी गई, वहीं कई ऐसे राज्य भी थे जिन्हें संघ की निगेटिव मार्किंग से गुजरना पड़ा, इन राज्यों में राजस्थान, उत्तराखंड व असम के नाम लिए जा सकते हैं। संघ का अपना आकलन है कि 'अगर राजस्थान व उत्तराखंड में सब बदस्तूर ऐसा ही चलता रहा तो अगली बार वहां भाजपा की वापसी मुश्किल हो जाएगी।' असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा की कामकाज की शैली व उनके अड़ियल व्यवहार को लेकर चिंता जताई गई है। संघ की सिफारिश थी कि 'भाजपा को हर राज्य में ऐसा मुख्यमंत्री चाहिए, जो सबको साथ लेकर चल सकने में सक्षम हो।' सूत्रों की मानें तो मुख्यमंत्रियों की इस रेटिंग चार्ट को भाजपा के बड़े नेताओं के हवाले कर दिया गया है और उनसे आग्रह किया गया है कि 'सही वक्त आने पर शीर्ष सही निर्णय लेने से पीछे न हटें।' आने वाले कुछ दिनों में भाजपा अध्यक्ष नितिन नबीन की नई टीम का ऐलान हो सकता है, इसकी घोषणा पिछले काफी समय से लंबित पड़ी है। जैसा कि सूत्र खुलासा करते हैं कि नितिन की यह नई टीम युवा प्रतिभाओं से लैस होगी, इसे बैलेंस करने के लिए कुछ पुराने अनुभवी चेहरों को भी इसमें बरकरार रखा गया है, जैसे महासचिवों की नई टीम में विनोद तावड़े और सुनील बंसल जैसे अनुभवी रणनीतिकारों की कुर्सी सलामत रह सकती है। सबसे ज्यादा कयास भाजपा के संगठन महामंत्री बीएल संतोष को लेकर लग रहे हैं, माना जा रहा है कि भाजपा के बड़े नेता संतोष के कामकाज के तरीकों से कतई खुश नहीं रहे हैं, खास कर कर्नाटक में उनके अनावश्यक हस्तक्षेप और भूमिका पर सदैव अंगुली उठी है, पर कहा जाता है कि उन्हें आने वाले दशहरा तक का अभयदान मिल गया है और ऐसा संघ की संस्तुति पर हुआ है। संघ का मानना है कि इस दशहरे पर जब संघ के 100 साल पूरे होने का कार्यक्रम अपनी इतिश्री को प्राप्त करेगा, उसके बाद ही बीएल संतोष को बदला जा सकता है, क्योंकि वे काफी पहले से संघ के 100 साल पूरे होने के कार्यक्रम को सफल बनाने की तैयारियों में जुटे हैं। उन्होंने लगातार संघ व भाजपा में इस आशय का संवाद सेतु बनाने का काम किया है, पर अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि अगर दशहरा के तुरंत बाद बीएल की विदाई होती है तो उनकी जगह कौन लेगा? फिलहाल दो नामों की बेहद चर्चा है जो संगठन महामंत्री पद के प्रबल दावेदार हो सकते हैं, इनमें से पहला नाम ?शिवप्रकाश का चल रहा है जो फिलवक्त भाजपा के संयुक्त संगठन महामंत्री हैं और बीएल संतोष के साथ कंधे से कंधा मिला कर अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन कर रहे हैं। स्मरण रहे कि संघ ने अपने इस स्वयंसेवक को सन् 2014 में भाजपा के साथ जोड़ा था और ये अमित शाह और जेपी नड्डा दोनों के भाजपाध्यक्षों के साथ काम कर चुके हैं। दूसरा नाम संघ के 54 वर्षीय संयुक्त महासचिव अतुल लिमये का लिया जा रहा है। वे पेशे से एक इंजीनियर हैं जिन्होंने इस दफे महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में भाजपा नीत महायुति की विजयश्री दिलवाने में एक महती भूमिका निभाई थी। बांकीपुर उपचुनाव भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नबीन के लिए अब प्रतिष्ठा का चुनाव बन गया है। हालांकि भाजपा ने भी इस लड़ाई में अपना सर्वस्व झोंक दिया है, वहां तक कि पर्दे के पीछे भी भाजपा उतनी ही सक्रिय है। सो जब राहुल चाहते थे कि पीके यहां से संयुक्त विपक्ष के उम्मीदवार हों तो तेजस्वी ने उनकी इस दलील को खारिज करते हुए यहां से राजद की अधिकृत उम्मीदवार रेखा गुप्ता को मैदान में उतार दिया। अब तेजस्वी के ऊपर यह आरोप लग रहे हैं कि उन्होंने इस सीट पर भाजपा के साथ एक 'टैक्टिकल अलायंस' कर लिया है क्योंकि इस सीट पर कायस्थ वोट सबसे निर्णायक है, इसके अलावा यहां बनिया, यादव व पिछड़े वोट भी काफी तादाद में है। रेखा कुमारी गुप्ता यहां की लोकल है, बनिया वोटर में उनकी अच्छी पैठ है, पिछड़े वोटरों में भी वह सेंध लगा सकने में सक्षम है। सो, ऐसे में जन सुराज पार्टी के प्रशांत किशोर को सिर्फ अगड़े वोटरों का ही आसरा रह जाएगा। सो,यहां की लड़ाई त्रिकोणात्मक हो सकती है, फिर भी पर्यवेक्षकों का मानना है कि यहां मुख्य लड़ाई भाजपा बनाम पीके की ही रहेगी। कांग्रेस पार्टी में अपनी सतत उपेक्षा से आहत चंडीगढ़ के सांसद मनीष तिवारी क्या कोई निर्णायक सियासी कदम उठा सकते हैं? पिछले कोई चार दशकों से लगातार कांग्रेस में बने रहने के बावजूद अब तिवारी के भगवा होने या भाजपा में जाने की अटकलें तेज हो गई हैं। इन कयासों को तब और पंख लग गए जब इसी शुक्रवार मनीष प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की चंडीगढ़ रैली के दौरान मंच पर उनके साथ दिखे। सनद रहे कि इस 17 जुलाई को चंडीगढ़ और मनीष के पूर्व संसदीय क्षेत्र आनंदपुर साहिब में पीएम मोदी द्वारा कई विकास परियोजनाओं का उद्घाटन किया गया था। हालांकि बाद में 'एक्स' पर मनीष ने खुद इस बात पर सफाई दे डाली। पर क्या यह महज इत्तफाक है कि इससे ठीक एक महीने पहले मनीष भाजपा के बड़े नेता से भी दिल्ली में मिले थे, तब वे अपने साथ अपनी संसदीय क्षेत्र में व्याप्त समस्याओं की एक लिस्ट लेकर दिल्ली पहुंचे थे। सूत्रों की मानें तो बातों-बातों में भाजपा के एक बड़े नेता ने मनीष से कहा कि 'आप अपने कार्यों की लिस्ट मुझे सौंप दें, आपका काम हो जाएगा, मुझे तो बस यह जानना था कि जहां रह कर आप इतनी घुटन महसूस कर रहे हैं, वहां से कब आजाद होंगे आप, हमारे दरवाजे आपके लिए खुले हैं।' तब मनीष ने हंस कर इस बात को टाल दिया था और कहा था कि 'वे पिछले चालीस सालों से कांग्रेसी हैं और कांग्रेसी ही रहना चाहते हैं।'

नागरिकता और चुनाव आयोग

देश का नागरिक कौन है और इसको साबित करने के लिए क्या किया जाना चाहिए। इस बात को लेकर आम नागरिकों में चर्चा गरम है। विभिन्न राज्यों में? निर्वाचन आयोग द्वारा करवाए जा रहे मतदाता सूचियों के विशेष पुनरीक्षण प्रक्रिया के चलते पूरा भ्रम फैला हुआ है और लोग यह समझ बैठे हैं कि अगर मतदाता सूचियों से उनका नाम हटा तो उनकी नागरिकता खतरे में पड़ जाएगी। इस भ्रम ने तब और व्यापक रूप धारण कर लिया जब माननीय अदालत ने एक मामले की सुनवाई के दौरान कहा कि आधार कार्ड, पैन कार्ड या वोटर आईडी होने से कोई भारतीय नागरिक नहीं बन जाता, यह दस्तावेज सिर्फ पहचान बताने के लिए है। फिर पासपोर्ट को विदेश मंत्रालय ने भी केवल यात्रा दस्तावेज माना। एक लोकतांत्रिक देश की जिम्मेदारी केवल कानून बनाने से कहीं ज्यादा उसे अपने नागरिकों के भरोसे को भी रक्षा करना होता है। अगर लोगों को यही डर सताने लगे कि सरकार द्वारा जारी किए गए दस्तावेज जो उनके पास दशकों से है वह बेकार है तो फिर सरकार और लोकतांत्रिक संस्थाओं दोनों पर भरोसा कमजोर होना स्वाभाविक है। पश्चिम बंगाल, बिहार में एसआईआर के अनुभव ने यह दिखाया कि छोटी से छोटी दस्तावेजी कमियों ने लाखों लोगों को प्रभावित किया। पुराने रिकार्ड में स्पैलिंग की गलतियों, तिथियों में अंतर या सरकारी दस्तावेजों के गायब होने की वजह से लोगों को मुश्किलों का सामना करना पड़ा। देश में आज भी गरीब समुदाय और गांव की जनसंख्या में दशकों पुराने दस्तावेज नहीं हैं। देश की सर्वोच्च अदालत ने अब पश्चिम बंगाल एसआईआर विवाद पर सुनवाई के दौरान स्पष्ट कर दिया कि चुनाव आयोग को नागरिकता तय करने का कोई अधिकार नहीं है। चुनाव आयोग का अधिकार केवल वोटर लिस्ट के पुनरीक्षण तक ही सीमित है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि कानून की? स्थति में कोई भ्रम नहीं है मतदाता सूची में किसी का नाम हटने से उसकी नागरिकता खत्म नहीं होती। नागरिकता का फैसला संबंधित मंत्रालय यानि गृह मंत्रालय का काम है। चुनाव आयोग की यह जिम्मेदारी है कि नागरिकता निर्धारण के लिए मामले संबंधित मंत्रालय को भेजे। चुनाव आयोग को यह देखना है कि मतदाता भारतीय नागरिक है या नहीं। क्योंकि चुनाव प्रक्रिया में भाग लेने का हक भारतीय नागरिकों को ही मिलना चाहिए। अगर किसी व्यक्ति का नाम संदिग्ध नागरिकता के आधार पर मतदाता सूची से हटाया जाता है तो उसे नागरिकता निर्धारित करने के लिए आवेदन करना होगा। सुप्रीम कोर्ट ने काफी हद तक नागरिकता को लेकर भ्रम दूर कर दिया है। एक तरफ जहां सत्ता पक्ष के लोग एसआईआर को जनता के पक्ष में बता रहे हैं, वहीं विपक्ष का आरोप है कि सत्ता हथियाने के लिए सत्ता पक्ष एसआईआर करवा रहे हैं और लाखों लोगों को मताधिकार से वंचित किया जा रहा है। यह भी वास्तविकता है कि देश में अवैध घुसपैठियों ने अपने पैन, राशन कार्ड और वोटर आईडी बनाए हुए हैं, जिनको मतदाता सूचियों से बाहर करना भी जरूरी है। हर नागरिक और उसके देश के बीच एक कानूनी रिश्ता होना और नागरिकता इस रिश्ते को बांधने वाली डोर का काम करती है। यही नागरिकता देश के नागरिकों को कई किस्म के अधिकार और सुविधाएं देती है। मूलभूत अधिकारों से लेकर वोट देने का अधिकार, कानूनी अधिकार, काम करने का अधिकार इत्यादि। समस्या यह है कि अगर आधार, ड्राइविंग लाइसेंस, राशन कार्ड, पासपोर्ट और मतदाता पहचान पत्र भी नागरिकता का प्रमाण नहीं है तो फिर कोई अपनी नागरिकता कैसे साबित करेगा। भारत का संविधान 26 जनवरी, 1950 को लागू हुआ था। आर्टिकल 5 से 11 आज़ाद भारत के शुरुआती नागरिकों के लिए नागरिकता के बारे में बताते हैं। आर्टिकल 5 उन लोगों को नागरिक मानता है जो संविधान के शुरू होने पर भारत में रहते थे। आर्टिकल 6 और 7 उन लोगों की नागरिकता के नियम बताते हैं जो पाकिस्तान से भारत आए थे और जो बंटवारे के बाद भारत से पाकिस्तान चले गए थे। आर्टिकल 11 संसद को नागरिकता से जुड़े मामलों पर कानून बनाने का पूरा अधिकार देता है। इस संवैधानिक अधिकार के तहत, संसद ने सिटिज़नशिप एक्ट, 1955 बनाया, जो भारतीय नागरिकता को कंट्रोल करने वाला मुख्य कानून बना हुआ है। इस एक्ट के तहत, भारतीय नागरिकता पांच मुख्य तरीकों से मिल सकती है - जन्म से, वंश से, रजिस्ट्रेशन से, देश में रहने से और इलाके में शामिल होने से। इसलिए, कानूनी तौर पर किसी व्यक्ति की नागरिकता सिर्फ इन्हीं आधारों पर तय होती है- सिर्फ किसी एक पहचान के दस्तावेज़ के होने या न होने से नहीं। पिछले कई सालों में नागरिकता कानून में कई बार बदलाव किए गए हैं जिससे जन्म से नागरिकता देने वाले नियमों में बड़े बदलाव हुए हैं। 26 जनवरी, 1950 और 1 जुलाई, 1987 के बीच, भारत में पैदा हुए हर व्यक्ति को भारतीय नागरिक माना जाता था, चाहे उनके माता-पिता किसी भी देश के हों। 1 जुलाई, 1987 और 3 दिसंबर, 2004 के बीच पैदा हुए लोगों के लिए, माता-पिता में से कम से कम एक का भारतीय नागरिक होना ज़रूरी था। 3 दिसंबर, 2004 के बाद कानून और सख्त हो गया। या तो माता-पिता दोनों भारतीय नागरिक होने चाहिए, या माता-पिता में से एक भारतीय नागरिक होना चाहिए, जबकि दूसरा गैर-कानूनी प्रवासी नहीं होना चाहिए। ये बदलाव साफ तौर पर दिखाते हैं कि नागरिकता उस समय लागू कानून के हिसाब से तय होती है न कि सरकार के किसी खास डॉक्यूमेंट के होने से। अब सवाल यह है कि अपने ही देश में नागरिकता सिद्ध करने वाला कोई एक प्रमाण पत्र नहीं है। केन्द्र सरकार को नागरिकता और पहचान से कानूनों को ज्यादा पारदर्शी बनाना चाहिए और देशभर को नेशनल सिटिजन रजिस्टर तैयार करना चाहिए और प्रत्येक नागरिक को विशिष्ट पहचान पत्र देना चाहिए ताकि उसके पास नागरिकता का पुख्ता प्रमाण हो।

तरणजीत सिंह संधू ने विरासत को आगे बढ़ाया

हम अक्सर कहते हैं कि मूल से ब्याज प्यारा होता है लेकिन आज हमारे सामने दिल्ली के लैफ्टिनेंट गवर्नर सरदार तरणजीत सिंह संधू ने एक सुन्दर उदाहरण दिया। जब एक पोता अपने दादा के आदर्शों, त्याग और बलिदान को पूरे समाज के सामने सम्मानपूर्वक प्रस्तुत करता है तब वह केवल पोता नहीं रहता, बल्कि अपनी विरासत का सच्चा संरक्षक बन जाता है। सरदार तरणजीत सिंह संधू द्वारा अपने दादा सरदार तेजा सिंह समुंदरी की शताब्दी मनाना इसी भावना का प्रतीक है। यह मुख्य समागम रकाबगंज गुरुद्वारा स्थित लक्खी शाह बंजारा हाल में आयोजित किया गया था। यह केवल पारिवारिक श्रद्धांजलि नहीं, बल्कि इतिहास, सेवा और मूल्यों को अगली पीढ़ी तक पहुंचाने का प्रयास है। आज एक पौत्र ने यह संदेश दिया है कि विरासत केवल सम्पत्ति की नहीं होती, बल्कि संस्कारों, आदर्शों और सेवा की भी होती है। मूल से ब्याज तो प्यारा होता है लेकिन जब ब्याज मूल का सम्मान बढ़ाए तभी उस रिश्ते की सच्ची सार्थकता होती है। सरदार तेजा सिंह समुंदरी (1882-1926) सिख समाज के महान धार्मिक एवं सामाजिक सुधारक थे। वे एसजीपीसी के संस्थापक सदस्यों में से एक थे और गुरुद्वारा सुधार आंदोलन के प्रमुख नेताओं में गिने जाते हैं। उन्होंने धार्मिक स्वतंत्रता, शिक्षा, सामाजिक सुधार और जनसेवा के लिए संघर्ष किया। ब्रिटिश शासन के दौरान जेल में रहते हुए 17 जुलाई, 1926 को सरदार तेजा सिंह समुंदरी जी की ऐतिहासिक शहादत हुई। सरदार तरणजीत सिंह संधू जी ने उनका श्रद्धांजलि दिवस मनाकर एक संदेश दिया है कि उनके दादा पूरे देश और सिख समाज के लिए एक प्रेरणा थे। इसलिए आज सभी को और विशेषकर युवाओं को तेजा सिंह समुंदरी के जीवन से निस्वार्थ सेवा, साहस, ईमानदारी और समाज के प्रति समर्पण की प्रेरणा लेनी चाहिए। दादा का सबसे बड़ा सम्मान फूल चढ़ाने से नहीं, ?बल्कि उनके बताए हुए मार्ग पर चलने और उनके आदर्शों को जीवित रखने से होता है। यही सच्ची श्रद्धांजलि है। सरदार तरणजीत सिंह संधू के पिता प्रो. बिशन सिंह समुंदरी प्रसिद्ध शिक्षाविद और गुरु नानक देव विश्वविद्यालय के प्रथम कुलपति रहे। तरणजीत ?संधू और उनकी पत्नी रीनत संधू जिन्हें उच्च शिक्षा प्राप्त है। दोनों भारतीय विदेश सेवा के वरिष्ठ राजनयिक रहे और अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत का प्रतिनिधित्व किया। मैं भी इस गौरवपूर्ण समारोह में शामिल हुई। हां सभी समाज के प्रमुख व्यक्तियों, दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता, मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति सूर्यकांत और दिल्ली के सभी मंत्री, एमएलए, प्रदेश अध्यक्ष हर्ष मल्होत्रा मौजूद थे। दिल्ली के सभी पूर्व अभी के गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के सभी लोग, पूर्व अध्यक्ष, वर्तमान अध्यक्ष, यहां तक कि हरियाणा सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के प्रधान भी मौजूद थे। युवा नेता थे, सबको वहां देख कर गुरु के चरणों में सिर झुकाया, प्रार्थना की, सरबत दा भला होवे और साथ ही हृदय में शांति मिली कि सरदार तरणजीत सिंह संधू जी ने सबको इकट्ठा कर दिया। यही सबकी तरफ से सच्ची श्रद्धांजलि थी। यही नहीं इससे संधू जी ने नई पीढ़ी को गुरुद्वारा सुधार आंदोलन के इतिहास से परिचित कराया। सिख संस्थाओं की लोकतांत्रिक परम्परा और सेवा की भावना को याद करवाया। समागम में भाई सरबजीत सिंह जी (पटना साहिब वाले) तथा भाई हरजिन्दर सिंह जी (श्रीनगर वाले) ने गुरबाणी, कीर्तन और शब्द गायन कर संगत को आध्यात्मिक रस से सराबोर किया। मुझे शब्द-कीर्तन सुनने में बहुत ही अच्छा लगता है।

सोनम वांगचुक और युवाओं का अनशन, छात्र राजनीति और ख़ामोश सरकार !

दिल्ली के जंतर मंतर पर नीट पेपर लीक मामले के बाद शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफ़े की मांग को लेकर कॉकरोच जनता पार्टी का प्रदर्शन चल रहा है। और मंगलवार को जिस दिन मैं वहां पहुंची उस दिन सोनम वांगचुक के अनशन का 17वां दिन था। बुधवार, 15 जुलाई को उनके अनशन का 18वां दिन हो गया। सोनम वांगचुक का वजन लगातार घट रहा है और सेहत बिगड़ रही है, लेकिन वे अब तक अनशन खत्म करने के मूड में नज़र नहीं आ रहे, मेन स्ट्रीम मीडिया की तरफ से बिल्कुल नज़र अंदाज वांगचुक का अनशन बीच में गुमनाम सा हो गया था लेकिन उनकी बिगड़ती सेहत ने सोशल मीडिया पर तूफ़ान मचा दिया। और एक बार फिर जंतर-मंतर का माहौल बदलने लगा, सिविल सोसाइटी के लोग, नेता,अभिनेता और सोशल मीडिया एन्फ्लुएंसर यहां नज़र आने लगे। जब हम यहां पहुंचे तो माहौल बहुत कुछ याद दिला रहा था। साल था 2011 और रामलीला मैदान में लोकपाल बिल को लेकर अन्ना हजारे का अनशन चल रहा था स्टेज पर एक चेहरा अपनी सफ़ेद शर्ट की तरह चमक रहा था, ये थे अभिनेता आमिर खान। मैदान में अच्छी खासी भीड़ थी और लगभग सभी न्यूज़ चैनल लगातार लाइव फीड काट रहे थे। एक लंबी और थका देने वाली ऑफिस की शिफ्ट के बाद मैं भी इस आंदोलन में पहुंची थी। रास्ते में लोगों का एक रेला साथ चल रहा था, एक पिता ने अपने बच्चे को कंधे पर बैठा रखा था और उस बच्चे के हाथ में तिरंगा झंडा था, ये तस्वीर मेरे ज़ेहन ने हमेशा के लिए क्लिक कर ली। मैं सोच रही थी कि आजादी की लड़ाई के लिए गांधी जी की पुकार पर लोग ऐसे ही घरों से निकले होंगे, हाथों में तिरंगा लिए। उस आंदोलन का हासिल क्या था हम सबने देखा। उस दौरान जो हीरो लग रहे थे आज वे क्या हैं और कहां हैं, सबकुछ समाज के सामने है। वहीं फिल्मों में विलेन का किरदार निभाने वाले सोनम वांगचुक की सेहत को लेकर अपनी चिंता ज़ाहिर कर रहे हैं, जो समाज के लिए एक सबक़ है कि रील और रियल लाइफ़ हीरो में कितना बड़ा अंतर होता है। बहरहाल, यहां बात मौजूदा आंदोलन की जो जंतर-मंतर पर चल रहा है, जैसे ही हम यहां पहुंचे जगह-जगह पोस्टर और बैनर लगे थे, छात्रों की टोलियां देशभक्ति तराने गा रही थीं, और सोनम वांगचुक के साथ ही लगातार अनशन कर रहे आइसा के छात्र एक अलग टैंट में बैठे थे। इसके अलावा लगातार धरना दे रहे छात्र अलग-अलग जमा थे। कई जगह पत्तियों के नीचे कैंप से लगे थे। ये छात्र सोनम वांगचुक के साथ शिक्षा व्यवस्था बदलने की लड़ाई लड़ रहे हैं। साथ दे रहे हैं भीषण गर्मी, बारिश और अब शदीद उमस में। जंतर-मंतर पर हमेशा धरना-प्रदर्शन होते रहते हैं, लेकिन ये प्रदर्शन कुछ अलग है और इसके परिणाम भी (चाहे वो जो भी हों) आगे के लिए एक बड़ा संदेश साबित होने वाले हैं। यहां हमने देखा कि हर तरफ भगत सिंह और बाबा भीम राव अंबेडकर की तस्वीरें लगी थीं और साथ ही मौजूद थे (अप्रत्यक्ष रूप से) आज़ादी की लड़ाई में योगदान देने वाले वे लोग जिनके लिखे नारे और तराने तो दोहराए जाते हैं लेकिन उन्हें भुला दिया गया,ऐसा ही एक नारा है इंक़लाब ज़िन्दाबाद जिसे लिखा था हसरत मोहानी ने। आज जब ये साबित करने की पुरज़ोर कोशिश चल रही है कि आज़ादी की लड़ाई में किसका योगदान था और किसका नहीं उस दौर में जंतर-मंतर पर इंक़लाब ज़िन्दाबाद और बोल को लब आज़ाद हैं तेरे जैसे तराने गाते हुए लोगों ने साबित कर दिया कि आज़ादी के लिए लड़ने वालों को कभी नहीं भूला जा सकता। ये तमाम पोस्टर, नारे और क्रिएटिव तरीक़े, और खुद को व्यक्त करते ये युवा याद दिला रहे थे कि आंदोलन का हासिल सिर्फ़ किसी मांग की पूर्ति नहीं होती बल्कि ये अभिव्यक्ति की आज़ादी की याद दिलाती है। वे भी उस वक़्त जब इसे हर तरह से दबा दिया गया हो। जिस दौर में छात्र राजनीति करना मुश्किल हो गया है, छात्रों पर मुक़दमे दर्ज हो रहे हैं उस दौर में अगर छात्र सोनम वांगचुक के साथ धरने पर बैठे हैं तो ये बड़ी बात है। यहां हमें आइसा की राष्ट्रीय अध्यक्ष नेहा मिली वे भी अपने साथियों के साथ पिछले 18 दिन से अनशन पर बैठी हैं, उनके साथ ही इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के मनीष कुमार और अंबेडकर यूनिवर्सिटी के छात्र अमीन भी अनशन कर रहे हैं । इन छात्रों की भी सेहत हर दिन बिगड़ती जा रही रही है, वजन घट है। जब हमने नेहा से पूछा कि एक न एक दिन ये आंदोलन खत्म हो जाएगा और उसके बाद जैसा की होता आया है, पुलिस-प्रशासन के निशाने पर आंदोलन में हिस्सा लेने वाले छात्र आ जाते हैं तो क्या वे इसके परिणाम भुगतने के लिए तैयार हैं? इसके जवाब में वे कहती हैं कि हम छात्र इस चीज़ से वाक़िफ़ हैं कि छात्र राजनीति की एक क़ीमत है वे आगे कहती हैं कि हम समझते हैं कि एक सोनम वांगचुक पर ढ्रग लग सकता है, एक उमर खालिद पर लोकतंत्र और समान नागरिकता के लिए प्रोटेस्ट करने पर,क्रम लग सकता है, तो स्टूडेंट एक्टिविज्म के क्या परिणाम हो सकते हैं इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के पीएचडी के छात्र और आइसा एक्टिविस्ट मनीष कुमार भी पिछले 18 दिन से अनशन पर बैठे हैं जब हमने उनसे पूछा कि वे क्या सोचते हैं छात्र राजनीति के बारे में और वे क्यों इस अनशन पर बैठे हैं तो उनका जवाब था नीट का सवाल ज्वलंत सवाल था, जिसने देश को झकझोर दिया, लेकिन उसके साथ ही देश के विश्वविद्यालयों को राष्ट्रीय शिक्षा नीति (हश्रक) के द्वारा बर्बाद किया जा रहा है, इलाहाबाद विश्वविद्यालय में पीएचडी की फ़ीस जो पांच सौ रुपए थी मैं उसी फ़ीस पर अपनी पीएचडी कर रहा हूं, अब वो फ़ीस बढ़कर 20 हज़ार रुपए हो गई है, और सालाना फ़ीस अलग से, साथ ही पब्लिक फंडड यूनिवर्सिटीज़ को बर्बाद किया जा रहा है, तो इस देश के जो शिक्षा मंत्री हैं उनसे सिर्फ़ नीट के स्टूडेंट परेशान नहीं हैं, हम विश्वविद्यालय के छात्र भी परेशान हैं, इलाहाबाद विश्वविद्यालय के छात्र इनके खिलाफ़ प्रोटेस्ट कर रहे हैं, लखनऊ विश्वविद्यालय के छात्र इनके खिलाफ़ प्रोटेस्ट कर रहे हैं, इसी सरकार का आंकड़ा है पिछले 10 सालों में 94 हज़ार स्कूल बंद हो गए, लाखों नौकरियां खत्म हो गई हैं, इस देश में शिक्षा और रोज़गार पर भाजपा की जो डबल इंजन की सरकार है उसका बुलडोज़र चल रहा है उन सब से हम पीड़ित हैं, नीट पेपर लीक के सवाल पर 22 छात्रों ने जो आत्महत्या की उनको न्याय दिलाने के सवाल पर, धर्मेंद्र प्रधान को इस्तीफ़ा देना पड़ेगा इस सवाल पर, ह्व्र जैसी एजेंसी जिसे पेपर लीक करवाने के लिए ही लाया गया है, उसे बंद किया जाए यही हमारा कहना है वहीं दिल्ली विश्वविद्यालय की छात्रा और चक्रुस की एक्टिविस्ट मुदिता का कहना है कि 25 दिन से हम यहां दिल्ली के जंतर-मंतर पर हैं, जिस देश में 25 दिन से छात्र और युवा सड़कों पर सो रहा है, जग रहा है, आंधी, तूफ़ान, बारिश के बीच वहां की सरकार के पास 25 मिनट भी नहीं है। इतने दिन में आज हमें ये बात समझ में आ गई है कि जब जवाबदेही सरकार और तंत्र के लिए आउट ऑफ़ सिलेबस हो जाए तो आंदोलन को हमें सिलेबस में लाना ही होता है वैसे ये बात हैरान करने वाली है कि जिस आंदोलन को क़रीब-क़रीब एक महीना होने जा रहा है और जिसमें 18 दिन से सोनम वांगचुक समेत कई युवा छात्र अनशन पर बैठे हैं आखिर अब तक सरकार की तरफ से उनसे कोई बातचीत क्यों नहीं की गई? आखिर अपने ही देश के लोगों से बातचीत न करने की क्या वजह हो सकती है। इस बीच सिविल सोसाइटी और चर्चित चेहरे सोनम वांगचुक से अनशन खत्म करने की अपील कर रहे हैं, उधर सीजेपी ने सोनम वांगचुक और छात्रों के समर्थन में 16 जुलाई को सामूहिक भूख हड़ताल का आह्वान किया है। कितनी अजीब बात है जिस देश ने अपने आंदोलनों और अनशन से अंग्रेज़ों को घुटने टेकने के लिए मजबूर कर दिया था आज उस देश में दुनिया भर में देश का नाम रौशन करने वाले सामाजिक कार्यकर्ता और पर्यावरणविद और छात्रों की जान पर बन आई है लेकिन सरकार की तरफ से बातचीत तो दूर उसकी कोई कोशिश भी दूर-दूर तक नज़र नहीं आती ।

सुप्रीम कोर्ट का बड़ा आदेश- अब हर राज्य में एक जैसी होगी समयपूर्व रिहाई की नीति

वैश्विक स्तरपर भारत की न्यायपालिका ने 16 जुलाई 2026 को एक ऐसा ऐतिहासिक और मानवीय कदम उठाया है,जो केवल जेल प्रशासन या कैदियों तक सीमित नहीं है,बल्कि यह भारतीय लोकतंत्र,संविधान, मानवाधिकार और न्याय व्यवस्था की संवेदनशीलता का भी प्रतीक बन गया है। सुप्रीम कोर्ट की न्यायमूर्ति विक्रम नाथ और न्यायमूर्ति संदीप मेहता की पीठ ने राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा दायर जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए देश के सभी राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों को निर्देश दिया कि वे तीन महीने के भीतर 70 वर्ष से अधिक आयु के, गंभीर एवं लाइलाज बीमारियों से पीड़ित तथा शारीरिक रूप से अक्षम कैदियों की समयपूर्व अथवा अनुकंपा के आधार पर रिहाई के लिए एक समान, व्यापक, पारदर्शी और मानवीय नीति तैयार करें।यह आदेश भारतीय न्यायिक इतिहास में इसलिए भी विशेष महत्व रखता है क्योंकि पहली बार सर्वोच्च न्यायालय ने पूरे देश में एकरूपता लाने के उद्देश्य से स्पष्ट समयसीमा निर्धारित की है। मैं एडवोकेट किशन सनमुखदास भावनानी गोंदिया महाराष्ट्र अधिवक्ता होने के नाते इस आर्टिकल के माध्यम से आम जनता को जानकारी देना चाहूंगा कि भारतीय संविधान का मूल दर्शन केवल अपराधियों को दंडित करना नहीं,बल्कि उन्हें सुधार का अवसर देना भी है।संविधान का अनुच्छेद 21 प्रत्येक व्यक्ति को गरिमा के साथ जीवन जीने का अधिकार प्रदान करता है। यह अधिकार जेल की चारदीवारी के भीतर भी समाप्त नहीं होता। यदि कोई व्यक्ति जीवन के अंतिम पड़ाव पर है, कैंसर, एड्स,अंतिम चरण की किडनी या अन्य असाध्य बीमारी से जूझ रहा है अथवा ऐसा दिव्यांग है जो अपना दैनिक कार्य स्वयं नहीं कर सकता, तो उसके साथ मानवीय व्यवहार करना एक सभ्य लोकतंत्र का नैतिक और संवैधानिक दायित्व है। सुप्रीम कोर्ट का यह आदेश इसी संवैधानिक दर्शन को व्यावहारिक रूप देने की दिशा में उठाया गया एक निर्णायक कदम है।अदालत ने इस दलील को स्वीकार किया कि गंभीर रूप से अक्षम और मृत्यु शय्या पर पड़े कैदियों को जेल में बंद रखना न केवल क्रूरता है,बल्कि यह देश के नागरिकों को मिलने वाले समानता के अधिकार (अनुच्छेद 14) और जीवन के अधिकार (अनुच्छेद 21) का भी खुला उल्लंघन है।इसका उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि जब कोई बुजुर्ग या गंभीर रूप से बीमार कैदी जेल से बाहर आए, तो उसे अचानक लावारिस न छोड़ दिया जाए। रिहाई के बाद भी उसे निरंतर चिकित्सा सहायता मिलती रहे, यदि उसका परिवार उसे अपनाने से इनकार कर दे तो उसे वृद्धाश्रम या सरकारी आश्रय गृहों में जगह मिले, और सामाजिक कल्याण योजनाओं के माध्यम से उसे वित्तीय सहायता या पेंशन मिल सके। यह समग्र दृष्टिकोण इस फैसले को एक सामान्य अदालती आदेश से ऊपर उठाकर एक महान सामाजिक सुधार और मानवीय क्रांति का दस्तावेज बनाता है, जिसकी गूंज आगामी 19 जनवरी 2027 को होने वाली सुनवाई में देश के सामने होगी। साथियों बात अगर हम देश में अभी तक समयपूर्व रिहाई की व्यवस्था को समझने की करें तो यह प्रत्येक राज्य में अलग-अलग नियमों पर आधारित रही है। कहीं कैदी को 14 वर्ष बाद विचार का अवसर मिलता है, कहीं 20 वर्ष बाद, तो कहीं अनेक प्रशासनिक औपचारिकताओं के कारण पात्र कैदियों की फाइलें वर्षों तक लंबित रहती हैं। कई बार मेडिकल रिपोर्ट समय पर नहीं बनती, कई बार जेल प्रशासन और गृह विभाग के बीच पत्राचार में महीनों निकल जाते हैं,तो कहीं राजनीतिक अथवा प्रशासनिक उदासीनता के कारण आवेदन फाइलों में दबे रह जाते हैं।परिणामस्वरूप अनेक बुजुर्ग और गंभीर बीमार कैदी न्याय मिलने से पहले ही जेल में दम तोड़ देते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने इस असमानता और प्रशासनिक ढिलाई को संविधान की भावना के विपरीत माना है।अदालत ने स्पष्ट किया कि यह आदेश सभी कैदियों के लिए नहीं है। इसका उद्देश्य केवल उन विशेष परिस्थितियों वाले कैदियों के लिए मानवीय राहत सुनिश्चित करना है जो 70 वर्ष से अधिक आयु के हैं, जिनकी बीमारी लाइलाज है या जो गंभीर शारीरिक अक्षमता के कारण सामान्य जीवन जीने में असमर्थ हैं। ऐसे मामलों में राज्य सरकारें चिकित्सकीय परीक्षण, सुरक्षा मूल्यांकन तथा अन्य कानूनी पहलुओं पर विचार करते हुए समयपूर्व अथवा अनुकंपा के आधार पर रिहाई का निर्णय लेंगी। अर्थात यह स्वतः रिहाई का आदेश नहीं बल्कि पारदर्शी और समयबद्ध निर्णय प्रक्रिया सुनिश्चित करने का निर्देश है।इस निर्णय का सबसे महत्वपूर्ण पक्ष यह है कि सुप्रीम कोर्ट ने पूरे देश में एक समान नीति बनाने पर जोर दिया है। साथियों, आज तक विभिन्न राज्यों की नीतियों में इतनी अधिक भिन्नता रही है कि समान परिस्थितियों वाले दो कैदियों को केवल अलग- अलग राज्यों में होने के कारण अलग-अलग व्यवहार का सामना करना पड़ता था। न्याय के सिद्धांत के अनुसार समान परिस्थितियों में समान व्यवहार होना चाहिए। यही कारण है कि अदालत ने राष्ट्रीय स्तर पर एकरूपता लाने का सटीक निर्देश दिया है।डिजिटल गवर्नेंस को बढ़ावा देने की दिशा में भी यह आदेश अत्यंत महत्वपूर्ण है। अदालत ने निर्देश दिया है कि समयपूर्व रिहाई की पूरी प्रक्रिया को ई-प्रिज़न्स पोर्टल से जोड़ा जाए।इससे आवेदन जमा होने से लेकरमेडिकल बोर्ड की रिपोर्ट, जेल प्रशासन की अनुशंसा,गृह विभाग की स्वीकृति और अंतिम निर्णय तक प्रत्येक चरण डिजिटल रूप से दर्ज होगा। इससे न केवल पारदर्शिता बढ़ेगी बल्कि भ्रष्टाचार,फाइलों के गायब होने,अनावश्यक देरी और जवाबदेही की कमी जैसी समस्याओं पर भी प्रभावी नियंत्रण लगेगा। यदि किसी स्तरपर आवेदन लंबित रहेगा तो यह स्पष्ट होगा कि देरी किस अधिकारी या विभाग के स्तर पर हुई है। साथियों, डिजिटल मॉनिटरिंग का यह मॉडल भारत में न्यायिक प्रशासन के आधुनिकीकरण का उत्कृष्टउदाहरण बन सकता है।जिस प्रकार आयकर, पासपोर्ट,भूमि अभिलेख, जीएसटी और न्यायालयों की ई-फाइलिंग प्रणाली ने प्रशासन को अधिक पारदर्शी बनाया है, उसी प्रकार जेल प्रशासन में डिजिटल निगरानी भविष्य में व्यापक सुधारों का मार्ग प्रशस्त कर सकती है।सुप्रीम कोर्ट ने केवल निर्देश देकर अपने दायित्व की औपचारिकता पूरी नहीं की है। उसने इस पूरे मामले की निरंतर निगरानी का भी निर्णय लिया है।अदालत ने सभी राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों को छह महीने के भीतर अनुपालन हलफनामा प्रस्तुत करने का निर्देश दिया है। इसमें यह स्पष्ट करना होगा कि नीति बनाई गई या नहीं, उसे अधिसूचित किया गया या नहीं, कितने मामलों पर विचार हुआ और कितने पात्र कैदियों को सटीकता से रिहा किया गया। साथियों, इस मामले की अगली सुनवाई 19 जनवरी 2027 को निर्धारित की गई है,जब सर्वोच्च न्यायालय स्वयं प्रत्येक राज्य की प्रगति की समीक्षा करेगा। यह दर्शाता है कि न्यायपालिका इस विषय को केवल सैद्धांतिक नहीं बल्कि व्यावहारिक परिणामों तक पहुँचाना चाहती है।यह निर्णय भारतीय जेलों की गंभीर समस्या अत्यधिक भीड़ को कम करने की दिशा में भी सहायक हो सकता है। देश की अनेक जेलें अपनी स्वीकृत क्षमता से कहीं अधिक कैदियों को रखने के लिए विवश हैं। भीड़भाड़ के कारण स्वास्थ्य सेवाएं, स्वच्छता, सुरक्षा, मानसिक स्वास्थ्य और पुनर्वास जैसी व्यवस्थाएं प्रभावित होती हैं। यदि वास्तव में अति वृद्ध, असाध्य रोगग्रस्त और अक्षम कैदियों के मामलों का समयबद्ध समाधान होता है तो जेलों पर दबाव कम होगा और प्रशासन उपलब्ध संसाधनों का बेहतर उपयोग कर सकेगा। साथियों, आर्थिक दृष्टि से भी यह निर्णय महत्वपूर्ण है। गंभीर बीमार कैदियों के इलाज पर राज्य सरकारों को बड़ी राशि खर्च करनी पड़ती है। कई मामलों में जेल अस्पताल पर्याप्त नहीं होते और उन्हें बाहरी अस्पतालों में भर्ती कराना पड़ता है, जहां सुरक्षा व्यवस्था पर भी अतिरिक्त व्यय होता है। यदि ऐसे कैदियों को कानून के अनुरूप मानवीय आधार पर रिहा किया जाता है तो सरकारी संसाधनों का अधिक प्रभावी उपयोग संभव होगा।

स्वामी, प्रकाशक, मुद्रक विजय कुमार भाटी ने वन्दना ऑफसेट प्रिन्टर्स, ए-9, सत्या पैलेसमेंट एक्स. दिल्ली-33, से मुद्रित कर कार्यालय, बी-2/370, सुल्तानपुरी, दिल्ली-86 से प्रकाशित किया सम्पादक : विजय कुमार भाटी, मो० : 09582093548 समाचार पत्र में प्रकाशित सामग्री से संपादक का सहमत होना आवश्यक नहीं विवादास्पद केवल दिल्ली कोर्ट में होंगे। (DELHIN/2014/[illegible])

सभासदों के इस्तीफे पर उठे सवाल, कुछ दिन पहले तक कर रहे थे अध्यक्ष की तारीफ

सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे इस्तीफा पत्र और पुरानी पोस्ट, अचानक बदले सुर को लेकर तरह-तरह की चर्चाएं

महराजगंज।

जिले की निचलौल नगर पंचायत में सभासदों द्वारा दिए गए इस्तीफे के बाद राजनीतिक हल्कों और सोशल मीडिया पर चर्चाओं का दौर तेज हो गया है। इस्तीफा देने वाले कई सभासदों के सुर में आए अचानक बदलाव को लेकर लोग सवाल उठा रहे हैं। चर्चा का विषय यह है कि जिन सभासदों ने नगर पंचायत अध्यक्ष के खिलाफ मोर्चा खोलते हुए इस्तीफा दिया है, उनमें से कई ने कुछ घंटे और कुछ दिन पहले तक अध्यक्ष के कार्यों की सोशल मीडिया पर खुलकर सराहना करते नहीं थक रहे थे।

उन्होंने विभिन्न विकास कार्यों और जनहित के कार्यों की प्रशंसा करते हुए पोस्ट साझा करते हुए आभार एंव धन्यवाद दे रहे थे। अब उन्हीं सभासदों के इस्तीफा पत्र और अध्यक्ष की तारीफ वाली पुरानी सोशल मीडिया पोस्ट को लोग एक साथ वायरल कर कई सवाल खड़ा कर रहे है।

इससे लोगों के बीच यह सवाल उठ रहा है कि आखिर ऐसा क्या हुआ कि इतने कम समय में सभासदों का सुर पूरी तरह बदल गया। अचानक हुए इस बदलाव के पीछे के कारणों को लेकर तरह-तरह के कयास लगाए जा रहे है। सोशल मीडिया पर भी इस पूरे घटनाक्रम को लेकर बहस छिड़ी हुई है। लोग वायरल पोस्ट और इस्तीफा पत्र साझा कर सभासदों के बदले रुख पर अपनी-अपनी प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं। हालांकि, सभासदों की ओर से इस्तीफे के पीछे के कारणों को लेकर जो भी आधिकारिक पक्ष सामने आएगा, उसके बाद ही पूरे मामले की वास्तविक स्थिति स्पष्ट हो सकेगी। उपरोक्त खबर सोशल मीडिया पर प्रसारित इस्तीफे के पत्र और सभासदों के द्वारा पूर्व में किए गए अध्यक्ष के कार्यों की तारीफ पर लोगों द्वारा प्रतिक्रिया पर आधारित है।

रोटरी क्लब ने 400 से अधिक पौधे नि:शुल्क वितरित किए, पर्यावरण संरक्षण का दिया संदेश

कसया, कुशीनगर।

पर्यावरण संरक्षण और हरित भविष्य के संकल्प के साथ रोटरी क्लब कुशीनगर ने रविवार को कसया स्थित गांधी चौक पर नि:शुल्क पौधा वितरण अभियान आयोजित किया। अभियान के दौरान विभिन्न प्रजातियों के 400 से अधिक पौधों का वितरण किया गया। पौधे लेने के लिए बड़ी संख्या में लोग गांधी चौक पहुंचे और अपने घर, विद्यालय, प्रतिष्ठान तथा सार्वजनिक स्थलों पर पौधारोपण करने का संकल्प लिया। रोटरी क्लब के सह संरक्षक वाहिद अली ने बताया कि पिछले वर्ष की तरह इस वर्ष भी लोगों को अधिक से अधिक पौधारोपण के लिए प्रेरित करने के उद्देश्य से यह अभियान चलाया गया है।

अध्यक्ष अजय कुमार सिंह ने बताया कि अभियान के तहत फलदार, छायादार एवं अन्य उपयोगी प्रजातियों के 400 से अधिक पौधे नि:शुल्क वितरित किए गए। लोगों के उत्साह को देखते हुए भविष्य में भी ऐसे कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। सचिव दुर्गेश चतुर्वेदी ने कहा कि रोटरी क्लब पर्यावरण संरक्षण के लिए निरंतर जनजागरूकता अभियान चलाता रहेगा। उन्होंने लोगों से केवल पौधे लगाने ही नहीं, बल्कि उनकी नियमित देखभाल कर उन्हें वृक्ष बनने तक संरक्षित रखने की अपील की। वक्ताओं ने कहा कि बढ़ते प्रदूषण, जलवायु परिवर्तन और घटते हरित क्षेत्र के बीच प्रत्येक व्यक्ति यदि कम से कम एक पौधा लगाकर उसका संरक्षण करे, तो आने वाली पीढ़ियों को स्वच्छ और सुरक्षित वातावरण दिया जा सकता है। इस अवसर पर कोषाध्यक्ष अखिलेश शर्मा, वरिष्ठ उपाध्यक्ष विजय कृष्ण द्विवेदी, उपाध्यक्ष सदरे आलम, दिनेश यादव, डॉ. श्याम बिहारी जायसवाल, निदेशक अरुण वर्मा, अमित श्रीवास्तव, सह सचिव सुनील सिंह, अमरेंद्र नारायण सिंह, मीडिया प्रभारी रंजीत श्रीवास्तव, विजय कुमार गुप्ता, इम्तियाज आलम, महेंद्र तिवारी, आशीष अग्रवाल, फौजिया परवीन, आदिल सहित रोटरी क्लब के अनेक सदस्य एवं नगरवासी उपस्थित रहे।

डीएम ने किया झुलनीपुर बैराज और नारायणी तटबंधों का निरीक्षण

31 गांवों की 70,000 हेक्टेयर भूमि की सुरक्षा से जुड़ा है छितौनी तटबंध, वाटर टूरिज्म की संभावनाएं तलाशने को कहा

महराजगंज।

मानसून के दृष्टिगत जनपद में बाढ़ सुरक्षा व्यवस्था को पुख्ता करने के लिए जिलाधिकारी गौरव सिंह सोगरवाल ने तहसील निचलौल क्षेत्र स्थित झुलनीपुर बैराज और नारायणी नदी के दाएं किनारे बने विभिन्न तटबंधों का स्थलीय निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान डीएम ने तटबंधों की मजबूती, मरम्मत कार्य और आपातकालीन तैयारियों का जायजा लिया। साथ ही सिंचाई विभाग और राजस्व अधिकारियों को अलर्ट मोड में रहने के निर्देश दिए।

जिलाधिकारी ने सबसे पहले नारायणी छितौनी तटबंध का निरीक्षण किया। तटबंध के टॉप पर बनी सड़क और दोनों ओर के ढाल की स्थिति देखकर उन्होंने संतोष व्यक्त किया। उन्होंने पाया कि तटबंध की संरचना ठीक है, लेकिन बरसात के दौरान किसी भी स्थिति से निपटने के लिए अतिरिक्त तैयारी जरूरी है। डीएम ने सिंचाई विभाग के अधिकारियों को निर्देश दिया कि तटबंध पर पर्याप्त मात्रा में मिट्टी का स्टॉक रखा जाए।

साथ ही रेंटकट सुदृढ़ीकरण का कार्य गुणवत्तापूर्ण और समय से पूरा किया जाए, ताकि जलस्तर बढ़ने पर त्वरित कार्रवाई की जा सके।सिंचाई विभाग के अधिकारियों ने बताया कि नारायणी छितौनी तटबंध से जनपद के 31 गांवों की लगभग 70,000 हेक्टेयर कृषि भूमि लाभान्वित होती है।

यह तटबंध क्षेत्र के लिए जीवनरेखा है। इसके बाद जिलाधिकारी ने सपार संख्या 01 पर चल रहे कंक्रीट ब्लॉक द्वारा लॉन्चिंग एप्रन और स्लोप पिचिंग के कार्य का निरीक्षण किया। उन्होंने कार्य की गुणवत्ता परखी और निर्देश दिया कि कार्य में किसी प्रकार की लापरवाही न बरती जाए।

निरीक्षण के दौरान जिलाधिकारी ने उक्त स्थल को नारायणी पूजा स्थल के रूप में विकसित करने के लिए संबंधित अधिकारियों को निर्देशित किया। उन्होंने कहा कि धार्मिक आस्था से जुड़े इस स्थल को साफ-सुथरा और सुव्यवस्थित किया जाए। साथ ही जिलाधिकारी ने नारायणी नदी में वाटर टूरिज्म की संभावनाओं के दोहन के लिए कार्ययोजना बनाने के निर्देश भी दिए। उन्होंने कहा कि प्राकृतिक सुंदरता और धार्मिक महत्व को देखते हुए यहां पर्यटन को बढ़ावा दिया जा सकता है, जिससे स्थानीय लोगों को रोजगार भी मिलेगा। जिलाधिकारी ने बारिश को देखते हुए सिंचाई विभाग सहित राजस्व, पुलिस और अन्य संबंधित विभागों को अलर्ट रहने को कहा। उन्होंने कहा कि तटबंधों की सतत निगरानी सुनिश्चित की जाए। गश्त बढ़ाई जाए और कहीं भी रिसाव, कटान या अन्य समस्या मिलने पर तत्काल सूचना देकर त्वरित कार्रवाई करते हुए समस्या का निवारण सुनिश्चित किया जाए। उन्होंने बाढ़ चौकियों को सक्रिय करने, आवश्यक सामग्री की उपलब्धता और कर्मचारियों की ड्यूटी रोस्टर बनाने के भी निर्देश दिए। निरीक्षण के दौरान तहसीलदार सदर अमित सिंह, अधिशासी अभियंता सिंचाई राजीव कपिल सहित सिंचाई विभाग, राजस्व विभाग और स्थानीय प्रशासन के अन्य अधिकारी उपस्थित रहे।

भटनी स्टेशन से शराब तस्कर गिरफ्तार, 17.1 लीटर अवैध अंग्रेजी शराब बरामद

भटनी देवरिया।

जीआरपी भटनी ने रेलवे स्टेशन के प्लेटफार्म संख्या-1 के पूर्वी छोर पर चेकिंग के दौरान एक शराब तस्कर को गिरफ्तार किया। उसके कब्जे से 17.1 लीटर अवैध अंग्रेजी शराब बरामद हुई, जिसकी अनुमानित कीमत 20,300 रुपये बताई गई है। गिरफ्तार आरोपी की पहचान बिहार के सारण (छपरा) जनपद के एकमा थाना क्षेत्र के विशुनपुरा कला निवासी प्रेम सिंह (36) के रूप में हुई। उसके बैग से 48 टेट्रा पैक 8पीएम स्पेशल, 22 टेट्रा पैक एसएनओएसकेआई (जामुन ब्रांड) तथा 6 बोतल ब्लेंडर प्राइड अंग्रेजी शराब बरामद की गई। पूछताछ में आरोपी ने स्वीकार किया कि वह उत्तर प्रदेश से शराब खरीदकर ट्रेन के माध्यम से बिहार ले जाकर अधिक दाम पर बेचता था। जीआरपी ने आरोपी के खिलाफ आबकारी अधिनियम की धारा 60 के तहत मुकदमा दर्ज कर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। यह कार्रवाई प्रभारी निरीक्षक अजय कुमार मौर्य के नेतृत्व में उपनिरीक्षक राजेश कुमार पाण्डेय, कांस्टेबल नितिन कुमार यादव, नरसिंह यादव और प्रमोद कुमार यादव की टीम ने की।

एक पेड़ मां के नाम अभियान में उत्कृष्ट योगदान पर अरविंद गुप्ता सम्मानित, पूर्वांचल स्कूल केयर एसोसिएशन ने किया अभिनंदन

पडरौना, कुशीनगर।

शहर के खिरिया टोला स्थित एक मैरिज हॉल में रविवार को पूर्वांचल स्कूल केयर एसोसिएशन द्वारा आयोजित सम्मान समारोह में संगठन के महासचिव एवं शिक्षाविद अरविंद गुप्ता का भव्य स्वागत एवं सम्मान किया गया। हाल ही में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक पेड़ मां के नाम अभियान के तहत 1100 से अधिक पौधे लगाकर उनका संरक्षण करने के लिए अरविंद गुप्ता को ?5,000 का प्रोत्साहन चेक एवं प्रशस्ति पत्र प्रदान कर सम्मानित किया था। इसी उपलब्धि पर एसोसिएशन ने उन्हें फूल-मालाओं से सम्मानित किया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि सदर विधायक मनीष जायसवाल ने कहा कि पौधे मानव जीवन का आधार हैं। पर्यावरण संरक्षण आज समय की सबसे बड़ी आवश्यकता है और वृक्षारोपण के साथ उनकी देखभाल करना भी उतना ही महत्वपूर्ण है। उन्होंने अरविंद गुप्ता के प्रयासों की सराहना करते हुए कहा कि ऐसे कार्य समाज के लिए प्रेरणादायी हैं। अपने संबोधन में अरविंद गुप्ता ने बताया कि कोरोना काल के दौरान जब

अधिकांश गतिविधियां ठप थीं, तब उन्होंने पर्यावरण संरक्षण का संकल्प लेते हुए 11 एकड़ भूमि में 1100 से अधिक पौधे लगाए। लगातार देखभाल और सिंचाई के कारण आज वे पौधे विकसित होकर हरियाली का स्वरूप ले चुके हैं। उन्होंने लोगों से अधिक से अधिक पौधे लगाने और उनकी सुरक्षा का संकल्प लेने की अपील की।

कार्यक्रम में एसोसिएशन के अध्यक्ष मनोज विश्वकर्मा ने कहा कि वृक्षारोपण ही पर्यावरण और मानव जीवन की सुरक्षा का सबसे प्रभावी माध्यम है। उन्होंने विद्यालयों से संबंधित मान्यता, आरटीई, यू-डायस सहित पांच सूत्रीय मांगों का ज्ञापन मुख्यमंत्री के नाम सदर विधायक मनीष जायसवाल को सौंपा। विधायक ने सभी मांगों पर सकारात्मक पहल और हरसंभव सहयोग का आश्वासन दिया। इस अवसर पर संगठन के संरक्षक बूंदल पाडेय, सचिव आशुतोष बांका, नचिकेता भट्ट, राजेश राय, वकील अंसारी, भाजपा नेता धनंजय तिवारी, राजीव यादव, आनंद सिंह, अमित कुमार शर्मा, पीयूष मिश्रा, समीर आलम, ओमप्रकाश गुप्ता सहित बड़ी संख्या में पदाधिकारी एवं शिक्षाविद उपस्थित रहे। कार्यक्रम का संचालन अमरनाथ यादव ने किया तथा अध्यक्षता अवधेश गुप्ता ने की। इस दौरान संगठन के अध्यक्ष मनोज विश्वकर्मा ने समर फील्ड पब्लिक स्कूल, पडरौना के प्रबंधक को ब्लॉक अध्यक्ष, पडरौना के पद पर मनोनयन की घोषणा भी की। समारोह का समापन पर्यावरण संरक्षण के संकल्प के साथ हुआ।

अभद्र भाषा का इस्तेमाल मात्र अश्लीलता नहीं, सुप्रीम कोर्ट का अहम फैसला

नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने एक महत्वपूर्ण फैसले में स्पष्ट किया कि केवल गाली-गलौज, अपमानजनक या अश्लील शब्दों का इस्तेमाल, चाहे वे कितने भी आपत्तिजनक या असभ्य क्यों न हों, को अपने आप में अश्लीलता नहीं माना जा सकता। न्यायमूर्ति संजय करोल और न्यायमूर्ति विपुल एम. पंचोली की पीठ ने यह टिप्पणी एक व्यक्ति की याचिका पर सुनवाई के दौरान की। याचिका में हाईकोर्ट के उस आदेश को चुनौती दी गई थी, जिसमें निचली अदालत द्वारा भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा 294 के तहत सुनाई गई सजा को बरकरार रखा गया था। पीठ ने कहा कि केवल अपमानजनक या अश्लील भाषा का इस्तेमाल कर देना, अपने आप में आईपीसी की धारा 294 के तहत अश्लीलता का अपराध नहीं बनता। शुक्रवार को दिए गए फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा, किसी कथन को अश्लील मानने के लिए यह साबित होना चाहिए कि वह कामुक प्रकृति का हो, कामुकता को बढ़ावा देने वाला हो और उसे सुनने या देखने वालों के मन को दूषित और भ्रष्ट करने की प्रवृत्ति रखता हो। अदालत ने कहा, अगर शिकायत में लगाए गए सभी आरोपों को पहली नजर में पूरी तरह सही भी मान लिया जाए, तब भी उन्हें अश्लील नहीं कहा जा सकता। पीठ ने कहा कि ऐसे शब्द, चाहे कितने भी अपमानजनक, अप्रिय या असभ्य हों, आईपीसी की धारा 294(बी) की आवश्यक शर्तों को पूरा नहीं करते। सुप्रीम कोर्ट ने कहा, यह किसी का भी मामला नहीं है कि ऐसे शब्दों के इस्तेमाल से सार्वजनिक स्थान पर मौजूद अन्य लोगों को परेशानी हुई, जबकि यह धारा लागू होने के लिए जरूरी शर्त है। शिकायतकर्ता के संबंध में भी ऐसा कोई आरोप नहीं है। ऐसे में हमें लगता है कि आईपीसी की धारा 294(बी) के तहत अपराध नहीं बनता। यह मामला अगस्त 2017 में तमिलनाडु में कृषि भूमि के विवाद से जुड़ा है, जिसमें याचिकाकर्ता और उसके साले के बीच विवाद हुआ था।

दो दिन बाद उसी जमीन के विवाद को लेकर याचिकाकर्ता की शिकायतकर्ता के भतीजे से भी कहासुनी हुई। अभियोजन पक्ष के अनुसार, जब शिकायतकर्ता बीच-बचाव करने आया तो याचिकाकर्ता ने उसे अश्लील गालियां दीं और जातिसूचक टिप्पणियां कीं। निचली अदालत ने याचिकाकर्ता को भारतीय दंड संहिता की धारा 294(बी) (अश्लीलता), धारा 326 (गंभीर चोट पहुंचाना) और धारा 506(2) (आपराधिक धमकी) के साथ-साथ अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम के प्रावधानों के तहत दोषी ठहराया था।

सपा सांसद का केन्द्र पर हमला, राम मंदिर चंदे पर उठाए गंभीर सवाल

नई दिल्ली। मॉनसून सत्र से पहले सर्वदलीय बैठक में समाजवादी पार्टी के सांसद धर्मेंद्र यादव ने महत्वपूर्ण बयान दिए। उन्होंने भारतीय जनता पार्टी पर 75 साल पुरानी लोकतांत्रिक व्यवस्था में अविश्वास का आरोप लगाया। साथ ही, राम मंदिर चंदे में कथित हेराफेरी पर सख्त कार्रवाई की मांग की। धर्मेंद्र यादव ने कहा कि भाजपा परिसीमन बिल लाने के लिए अत्यधिक बेताब है। उन्होंने सवाल किया कि देश की लोकतांत्रिक प्रणाली पर भाजपा को भरोसा क्यों नहीं है। समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता और अखिलेश यादव इस बिल का पहले भी विरोध करते रहे हैं। वे इसे रोकने के लिए अपनी पूरी ताकत लगा देंगे

रेड अलर्ट! उत्तराखंड में कुदरत का कहर, आज नर्सरी से 12 तक सभी स्कूलें बंद, रास्ते में अटके मानसरोवर यात्री

देहरादून। उत्तराखंड में कुदरत का कहर जारी है. लगातार हो रही मूसलाधार बारिश ने प्रदेश भर में हालात बिगाड़ दिए है. मौसम विभाग ने देहरादून, टिहरी और हरिद्वार समेत राज्य में भारी बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है. उत्तरकाशी, नैनीताल, चम्पावत, पौड़ी और ऊधम सिंह नगर में फिलहाल ऑरेंज अलर्ट है. हालात की गंभीरता को देखते हुए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मुख्य सचिव और सचिव आपदा प्रबंधन को हाई अलर्ट पर रहने के निर्देश दिए है. उन्होंने राहत-बचाव दलों को 24 घंटे मुस्तैद रहने और सड़क, बिजली व संचार जैसी बाधित सेवाओं को तुरंत बहाल करने को कहा है. आपदा प्रबंधन सचिव विनोद कुमार सुमन ने सभी विभागों को 24x7 अलर्ट मोड में रहने को कहा है. बच्चों की सुरक्षा को सर्वोपरि रखते हुए संवेदनशील जिलों में सोमवार को छुट्टी का ऐलान कर दिया गया है. चमोली, ऊधम सिंह नगर, अल्मोड़ा और पिथौरागढ़ में आंगनबाड़ी केंद्रों से लेकर कक्षा 1 से 12वीं तक के सभी स्कूल सोमवार को पूर्ण रूप से बंद रहेंगे. वहीं, देहरादून में डीएम आशीष चौहान ने कलेक्ट्रेट में सोमवार को लगने वाले समाधान दिवस को भी भारी बारिश के अलर्ट के मद्देनजर फिलहाल स्थगित कर दिया है.

मंदिर जाने वालों के लिए चेतावनी

राजधानी देहरादून में लगातार बारिश के कारण नदियों का जलस्तर तेजी से बढ़ रहा है. कैंट इलाके में टपकेश्वर महादेव मंदिर से होकर गुजरने वाली टोंस नदी अपने पूरे वेग (उफान) पर है. मंदिर प्रबंधन ने श्रद्धालुओं और स्थानीय लोगों से अपील की है कि वे नदी के आसपास बिल्कुल न जाएं.

कैलाश मानसरोवर यात्रा पर ब्रेक

पिथौरागढ़ में भारी बारिश और भूस्खलन ने कैलाश-मानसरोवर यात्रा रोक दी है. गर्बाधार में भारी लैंडस्लाइड के कारण लगातार दूसरे दिन बॉर्डर रोड बंद है. इसके चलते यात्रा का पहला दल फिलहाल बूंदी में फंसा हुआ है, जबकि चौथा दल रास्ता बंद होने के कारण निराश होकर बेस कैंप वापस लौट आया है. प्रशासन धारचूला और मानसरोवर यात्रा मार्गों की पल-पल की निगरानी कर रहा है.

संसद मार्च : सौरभ भारद्वाज बोले- मैं रहूंगा शामिल

नई दिल्ली। 20 जुलाई को सीजेपी के प्रस्तावित संसद मार्च से पहले दिल्ली में सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है. दिल्ली पुलिस ने साफ किया है कि संसद मार्च के लिए न तो कोई अनुमति मांगी गई है और न ही दी गई है. वहीं, आम आदमी पार्टी के दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष सौरभ भारद्वाज ने एबीपी न्यूज से खास बातचीत में कहा कि वह प्रस्तावित संसद मार्च में शामिल होंगे. दूसरी ओर, संसद के मानसून सत्र को देखते हुए दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने एडवाइजरी जारी की है और नई दिल्ली इलाके में कई सड़कों और चौराहों से बचने की सलाह दी है. सौरभ भारद्वाज ने दावा किया कि आंदोलन अब जंतर-मंतर तक सीमित नहीं रह गया है. उन्होंने कहा कि दिल्ली समेत कई राज्यों से बड़ी संख्या में युवा आंदोलन में शामिल होने पहुंच चुके हैं और कई लोग अभी भी रास्ते में हैं. धारा 163 लागू किए जाने पर सौरभ भारद्वाज ने कहा कि अब ऐसी पाबंदियों से कुछ नहीं होने वाला. उन्होंने सरकार से युवाओं को प्रधानमंत्री से मिलवाने और केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा लेने की मांग दोहराई. वहीं, 20 जुलाई के प्रस्तावित संसद मार्च पर उन्होंने कहा, हम तो आज ही आ गए है. केजरीवाल आएंगे या नहीं, मुझे नहीं पता, लेकिन मैं अभी से यहां हूं. दिल्ली पुलिस ने स्पष्ट किया है कि 20 जुलाई को प्रस्तावित संसद मार्च के लिए न तो आयोजकों की ओर से कोई अनुमति मांगी गई है और न ही किसी तरह की अनुमति दी गई है. पुलिस ने लोगों से कानून-व्यवस्था बनाए रखने में सहयोग करने की अपील की है. नई दिल्ली जिले के संसद मार्ग सब-डिवीजन के अधिकांश हिस्से में पहले से धारा 163 लागू है. इसके तहत बिना अनुमति सार्वजनिक सभा, पांच या उससे अधिक लोगों के एकत्र होने, जुलूस, प्रदर्शन, धरना, नारेबाजी और हथियार, लाठी-डंडे जैसी वस्तुएं लेकर चलने पर रोक है. यह आदेश 22 अगस्त 2026 तक प्रभावी रहेगा.

विपक्ष का वॉकआउट सिर्फ सांकेतिक था, सरकार चाहती है संसद में सार्थक चर्चा- किरेन रिजिजू

नई दिल्ली। केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा कि 19 जुलाई को सर्वदलीय बैठक के दौरान विपक्ष का वॉकआउट सांकेतिक था और इसे बहिष्कार नहीं माना जाना चाहिए। यह बैठक संसद के मॉनसून सत्र से पहले हुई, जो 20 जुलाई से शुरू होने वाला है। रिजिजू ने पत्रकारों से कहा कि इसे पूरे दिन की कार्यवाही के बहिष्कार के तौर पर नहीं देखा जाना चाहिए, यह सांकेतिक था। बैठक में तब बाधा आई जब विपक्ष के नेताओं ने हाल की राजनीतिक घटनाओं के विरोध में वॉकआउट किया; इन घटनाओं में 20 तृणमूल कांग्रेस सांसद और नेशनलिस्ट सिटिजन्स पार्टी ऑफ इंडिया के साथ-साथ ठाकरे शिवसेना के छह सांसद शामिल थे, जो शिवसेना में शामिल हो गए थे। उन्होंने आगे कहा कि दलों की संख्यात्मक शक्ति पर चर्चा की गई और इस बात पर जोर देते हुए कहा कि हम राजनीतिक दलों की संख्यात्मक शक्ति के आधार पर मामलों पर चर्चा करते हैं, लेकिन हम निश्चित रूप से किसी को भी उसके अधिकारों से वंचित नहीं कर सकते। बैठक के बाद, रिजिजू ने विपक्षी दलों से संसदीय कार्यवाही में बाधा न डालने का आग्रह किया और इस बात पर बल दिया कि सरकार विधेयकों पर गहन बहस चाहती है। उन्होंने जल्दबाजी में या अराजकता के बीच विधेयकों को पारित करने के आरोपों के खिलाफ चेतावनी दी। छोटी पार्टियों की चिंताओं पर बात करते हुए रिजिजू ने कहा कि छोटी पार्टियों के सदस्यों ने मांग की है कि उन्हें बोलने के लिए ज्यादा समय दिया जाए। इस पर हमने कहा है कि अगर संसद का सत्र ठीक से चलता है, तो सभी को बोलने का मौका मिलेगा। अगर कामकाज में रुकावट आती है, तो बोलने का मौका हाथ से निकल जाएगा। साथ ही, बाद में सरकार पर यह आरोप नहीं लगाया जाना चाहिए कि बिलों को बिना ज्यादा चर्चा के या हंगामे के बीच पास कर दिया गया। भारत सरकार पर ऐसे आरोप नहीं लगने चाहिए, क्योंकि सरकार सचमुच चाहती है कि चर्चा हो और बिलों को पास करने से पहले सभी लोग उन्हें ध्यान से देखें और परखें। सांकेतिक वॉकआउट में शामिल विपक्षी नेता बाद में बैठक में लौट आए। टीएमसी नेता महुआ मोइत्रा ने कहा कि आज कांग्रेस, समाजवादी पार्टी, DMK, JMM, आम आदमी पार्टी, नेशनल कॉन्फ्रेंस, वामपंथी दलों और शिवसेना समेत पूरे विपक्ष ने सर्वदलीय बैठक से विरोध स्वरूप वॉकआउट किया। ऐसा इसलिए किया गया क्योंकि तथाकथित NCPI (जो एक गैर-मान्यता प्राप्त पार्टी है) के मामले में, टेबल ऑफिस द्वारा दी गई सूची में ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस की सदस्य संख्या 28 दिखाई गई है। इन तथाकथित बागी 20 सांसदों के विलय को स्पीकर ने मंजूरी नहीं दी है।

ईरान ने मार गिराया अमेरिकी MQ-9 रीपर ड्रोन

अमेरिका और ईरान के बीच जारी सैन्य तनाव के बीच ईरान की इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स ने दावा किया है कि उसने रविवार को दक्षिण-पश्चिमी ईरान के अहवाज क्षेत्र में अमेरिकी MQ-9 Reaper ड्रोन को मार गिराया है। ईरान का कहना है कि उसकी वायु रक्षा प्रणाली ने अमेरिकी ड्रोन को देश के हवाई क्षेत्र में प्रवेश करते ही निशाना बनाया।

हालांकि, अमेरिकी रक्षा विभाग या अमेरिकी सेंट्रल कमांड की ओर से इस दावे की अभी तक आधिकारिक पुष्टि नहीं की गई है। इसलिए फिलहाल इस दावे की स्वतंत्र रूप से पुष्टि नहीं हो सकी है। ईरानी समाचार एजेंसी तसनीम के अनुसार, IRGC की एयरोस्पेस फोर्स ने ईरान के एकीकृत वायु रक्षा नेटवर्क की मदद से अमेरिकी MQ-9 Reaper ड्रोन को सफलतापूर्वक इंटरसेप्ट कर मार गिराया। ईरान का दावा है कि यह कार्रवाई उसकी हवाई सुरक्षा व्यवस्था का हिस्सा थी। ईरान के केंद्रीय खातम अल-अंबिया मुख्यालय के कमांडर मेजर जनरल अली अब्दोल्लाही ने कहा कि यदि अमेरिका ने किसी भी प्रकार की सैन्य आक्रामकता दिखाई तो ईरान उसकी ऐसी कीमत वसूल करेगा, जो पहले के सभी संघर्षों से कहीं अधिक भारी होगी। उन्होंने कहा कि ईरान की सैन्य शक्ति देश की सुरक्षा की सबसे बड़ी गारंटी है और अमेरिका क्षेत्र में अस्थिरता फैलाने की कोशिश कर रहा है। IRGC ने दावा किया कि उसने जॉर्डन के अल-अजराक स्थित अमेरिकी सैन्य अड्डे पर मिसाइल और ड्रोन हमला किया। हमले में दो लड़ाकू विमान और तीन अन्य

IRGC ने कहा- अगला हमला और भी विनाशकारी होगा

अमेरिकी विमान नष्ट करने का दावा किया। कुवैत के बंदर अल-अहमदी स्थित अमेरिकी ईंधन आपूर्ति केंद्र को निशाना बनाया। बहरीन के शेख ईसा एयरबेस और कथित खुफिया डेटा सेंटर पर भी हमला करने का दावा किया। कुवैत में अमेरिकी संचार केंद्र को भी नष्ट करने की बात कही। इन सभी दावों की स्वतंत्र पुष्टि अभी तक नहीं हुई है। दूसरी ओर, अमेरिकी सेंट्रल कमांड ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर जानकारी दी कि अमेरिकी सेना ने ईरान के खिलाफ लगातार सातवीं रात भी सैन्य अभियान जारी रखा।

शिक्षा के विरुद्ध है भाजपा- अखिलेश

लखनऊ। रामपुर की जौहर यूनिवर्सिटी के अस्तित्व पर इन दिनों संकट के बादल मंडरा रहे है, प्रशासन की तरफ से यूनिवर्सिटी के ध्वस्तीकरण से संबंधित आदेश के बाद यह मामला अब चर्चा का बड़ा चर्चा का विषय बन चुका है. उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने जौहर विश्वविद्यालय में पढ़ने वाले छात्रों और उनके अभिभावकों के नाम बड़ा संदेश दिया है. अखिलेश यादव ने कहा है कि जौहर यूनिवर्सिटी को बचाने की युवाओं और उनके अभिभावकों की मुहिम में, वह उनके साथ है. अखिलेश ने कहा कि, बदले की भावना में जल रही भाजपा सरकार जौहर यूनिवर्सिटी को अपनी संकीर्ण राजनीति का शिकार बनाने की कोशिश न करे. अखिलेश यादव ने कहा कि इस दुर्भावनापूर्ण पक्षपाती फैसले के खिलाफ, हमारे साथ हमारा छोटे-से-छोटा कार्यकर्ता, समर्थक, बड़े-से-बड़ा नेता और वो सब हजारों बच्चे व उनके मेहनतकश माता-पिता भी है, जिनके सपने पर बुलडोजर चलाने की निकृष्ट कोशिश भाजपा सरकार कर रही है. उन्होंने कहा कि, हर विश्वविद्यालय शिक्षा का मंदिर होता है, हम 'शिक्षा के मंदिर' को बचाने के लिए, देश भर से अपील करते है कि वो हमारे साथ आएं. अखिलेश यादव ने कहा कि, विश्वविद्यालय में हर समाज के बच्चे पढ़ते है, क्या भाजपा अब हर समाज के युवाओं के विरुद्ध हो गई है. भाजपा का अहंकार ही ये सब गलत काम करा रहा है. अगर कहीं कुछ कागजी कमी है भी तो उसके कागज पूरे करके यूनिवर्सिटी को बचाया जाए और स्टूडेंट्स के भविष्य को भी. उन्होंने कहा कि यहां गरीबों के बच्चे पढ़ते है, जिनके पास इतना पैसा नहीं होता कि वो भाजपाइयों की तरह अपने बच्चों को महंगे विश्वविद्यालय या विदेशों में पढ़ा सकें. जिनके न परिवार है न बच्चे, वो परिवारवालों का दर्द क्या जानें. अगर भाजपा के मन में बच्चों, युवाओं, उनके परिवार-परिजनों व समाज के लिए रत्ती भर भी सहानुभूति होती तो वो जुल्म और नाइंसाफी से भरी इस विध्वंसक कार्रवाई का तत्काल कोई विकल्प ढूंढती. उन्होंने कहा कि सच तो ये है कि भाजपा शिक्षा के ही विरुद्ध है क्योंकि शिक्षित लोग जागरूक और प्रगतिशील होते है, वो अन्याय के खिलाफ आवाज भी उठाते है।

पश्चिम बंगाल को मिली बड़ी सौगात, अमित शाह ने 700 करोड़ की दुनिया की सबसे बड़ी दही उत्पादन परियोजना की रखी आधारशिला

बंगाल। केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह ने रविवार को पश्चिम बंगाल में अमूल बंगाल डेयरी परियोजना के तहत दुनिया के सबसे बड़े दही उत्पादन संयंत्र की आधारशिला रखी। शाह ने न्यू टाउन स्थित विश्व बांग्ला कन्वेंशन सेंटर से हावड़ा में बनने वाले इस संयंत्र की आधारशिला डिजिटल माध्यम से रखी।

इस मौके पर मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी और अमूल ब्रांड के तहत डेरी उत्पादों का विपणन करने वाली गुजरात को-ऑपरेटिव मिल्क मार्केटिंग फेडरेशन (जीसीएमएमएफ) के वरिष्ठ अधिकारी मौजूद थे। करीब 700 करोड़ रुपये के निवेश से हावड़ा फूड पार्क में बनने वाली इस परियोजना की प्रतिदिन लगभग 30 लाख लीटर दूध प्रसंस्करण की क्षमता होगी। आधिकारिक बयान के अनुसार, संयंत्र में हर दिन करीब 1,000 टन दही और अन्य संवर्धित डेरी उत्पादों का उत्पादन किया जा सकेगा। इसके पूरा होने के बाद यह दुनिया की सबसे बड़ी दही उत्पादन इकाई बन जाएगी। बयान में कहा गया कि इस परियोजना से पश्चिम बंगाल के 1.25 लाख से अधिक डेरी किसानों को लाभ मिलने की उम्मीद है, जिनमें 30,000 से अधिक महिलाएं शामिल हैं। इससे किसानों को दूध के लिए स्थिर बाजार उपलब्ध होगा और राज्य में डेरी सहकारी नेटवर्क को मजबूती मिलेगी। यह परियोजना राज्य में डेरी बुनियादी ढांचे के विस्तार और मूल्यवर्धित दूध प्रसंस्करण को बढ़ावा देने के प्रयासों के तहत विकसित की जा रही है।

> शाह ने न्यू टाउन स्थित विश्व बांग्ला कन्वेंशन सेंटर से हावड़ा में बनने वाले इस संयंत्र की आधारशिला डिजिटल माध्यम से रखी। इस मौके पर मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी और अमूल ब्रांड के तहत डेरी उत्पादों का विपणन करने वाली गुजरात को-ऑपरेटिव मिल्क मार्केटिंग फेडरेशन (जीसीएमएमएफ) के वरिष्ठ अधिकारी मौजूद थे।

मायावती की अपील- महंगाई, बेरोजगारी, जनहित के मुद्दों पर हो चर्चा, संसद चले, हंगामा नहीं

लखनऊ। बहुजन समाज पार्टी (बसपा) की राष्ट्रीय अध्यक्ष मायावती ने सोमवार से शुरू हो रहे संसद के मानसून सत्र को स्वस्थ लोकतांत्रिक परंपराओं के अनुरूप शांतिपूर्ण एवं सुचारू ढंग से संचालित किए जाने का आह्वान किया है। मायावती ने रविवार को सोशल मीडिया मंच एक्स पर एक पोस्ट में कहा, देश महंगाई, गरीबी, बेरोजगारी, महिला सुरक्षा, पेपर लीक और अन्य गंभीर चुनौतियों का सामना कर रहा है। ऐसे में संसद का सत्र हंगामे और बार-बार के स्थगन की भेंट चढ़ने के बजाय इन मुद्दों के समाधान पर केंद्रित होना चाहिए। उन्होंने कहा कि संसद में जनहित से जुड़े सभी महत्वपूर्ण विषयों पर गंभीरता और संवेदनशीलता के साथ चर्चा होनी चाहिए, ताकि आम लोगों की समस्याओं के समाधान की दिशा में ठोस पहल हो सके। बसपा प्रमुख ने अयोध्या स्थित श्रीराम जन्मभूमि मंदिर में चढ़ावे की कथित चोरी के मुद्दे का भी उल्लेख करते हुए कहा कि इस मामले को लेकर व्यापक जनचर्चा और आक्रोश है। उनके अनुसार, इस विषय की गूंज सड़कों से लेकर अदालत तक सुनाई दे रही है और संसद में भी इस पर चर्चा होने की संभावना है। मायावती ने पश्चिम बंगाल की राजनीतिक स्थिति, राजस्थान में गर्भवती महिलाओं की मौत, विभिन्न राज्यों में महिला असुरक्षा, सरकारी योजनाओं में कथित भ्रष्टाचार, पुलिस मुठभेड़ों, अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई के दौरान बस्तियों के ध्वस्तीकरण तथा अन्य मुद्दों का भी जिक्र किया। उत्तर प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री ने कहा कि अमेरिका-इजराइल और ईरान के बीच जारी संघर्ष तथा रुपये के अवमूल्यन जैसे अंतरराष्ट्रीय और आर्थिक मुद्दों का भी भारत की अर्थव्यवस्था और जनजीवन पर प्रभाव पड़ रहा है।

संसद मार्च को लेकर टकराव- वांगचुक की पत्नी करेंगी प्रदर्शन की अगुवाई, पुलिस बोली- इजाजत नहीं, धारा 163 लागू

सरकारी अस्पताल में ही भर्ती रहेंगे सोनम वांगचुक, दिल्ली हाईकोर्ट ने अंतरिम राहत देने से किया इनकार

नई दिल्ली। दिल्ली उच्च न्यायालय ने रविवार को जलवायु कार्यकर्ता सोनम वांगचुक के सफदरजंग अस्पताल में जारी इलाज के मामले में दखल देने से इनकार कर दिया। न्यायमूर्ति मिनी पुष्करणा ने कहा कि इस चरण में सोनम वांगचुक को निजी अस्पताल में स्थानांतरित करने संबंधी उनकी पत्नी गीतांजलि जे. आंगमो की याचिका पर किसी अंतरिम आदेश की आवश्यकता नहीं है। मामले की अगली सुनवाई 24 जुलाई को होगी। शनिवार को भूख हड़ताल के 21वें दिन दिल्ली पुलिस वांगचुक को जंतर-मंतर से सफदरजंग अस्पताल ले गई थी। वांगचुक 28 जून से नीट परीक्षा में कथित अनियमितताओं और परीक्षा रद्द होने के बाद कई छात्रों द्वारा आत्महत्या किए जाने के विरोध में भूख हड़ताल कर रहे थे। रविवार को विशेष सुनवाई के दौरान न्यायमूर्ति पुष्करणा ने कहा कि सफदरजंग अस्पताल के डॉक्टर वांगचुक की लगातार निगरानी कर रहे हैं, और यह नहीं कहा जा सकता कि उनके खिलाफ किसी प्रकार की जबरदस्ती की जा रही है। न्यायाधीश ने यह भी कहा कि सरकार द्वारा वांगचुक को जंतर-मंतर से हटाकर सफदरजंग अस्पताल ले जाए जाने की कार्रवाई को मनमाना नहीं कहा जा सकता। न्यायमूर्ति पुष्करणा ने यह भी उल्लेख किया कि वांगचुक की पत्नी गीतांजलि आंग्मो, उनके भाई और रिश्तेदारों को उनसे 24 घंटे मिलने की अनुमति दी गई है। अदालत ने वांगचुक को निजी अस्पताल में स्थानांतरित करने के अनुरोध वाली आंग्मो की याचिका पर केंद्र सरकार, सफदरजंग अस्पताल और दिल्ली पुलिस को नोटिस जारी किया। अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल (एएसजी) चेतन शर्मा ने कहा कि इस मामले में किसी प्रकार के संदेह की कोई वजह नहीं होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि सफदरजंग अस्पताल के डॉक्टर वांगचुक की अच्छी तरह देखभाल कर रहे है, लेकिन उन्हें भी इलाज में सहयोग करना होगा। इस पर हस्तक्षेप के लिए डॉक्टरों का सहयोग करेंगे।

याचिकाकर्ता की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल ने अदालत को बताया कि वह चाहते है कि

विपक्षी नेता संसद में मुद्दा उठाने का वादा करें तो सोनम अनशन खत्म कर देंगे- पत्नी गीतांजलि

सोनम की पत्नी गीतांजलि ने रविवार को जंतर-मंतर पर कहा- अगर राजनीतिक दलों के नेता अस्पताल पहुंचकर वांगचुक से मिलें और भरोसा दें कि वे संसद में यह मुद्दा उठाएंगे, तो वह अपना अनशन समाप्त कर देंगे। सोनम वांगचुक की मांग शिक्षा व्यवस्था में जवाबदेही सुनिश्चित करने की है और वे चाहते हैं कि इस मुद्दे पर संसद में गंभीर चर्चा हो। यदि नेताओं की ओर से सकारात्मक आश्वासन मिलता है, तो वांगचुक अनशन खत्म कर देंगे।

अदालत ने कहा, यह कहने की आवश्यकता नहीं है कि यदि आवश्यक हुआ और यदि वह स्वयं ऐसा चुनते हैं, तो सोनम वांगचुक चिकित्सकीय वांगचुक को मेदांता अस्पताल स्थानांतरित किया जाए। सिब्बल ने इस बात पर जोर दिया कि वांगचुक किसी हिरासत में नहीं हैं। उन्होंने सवाल उठाया कि क्या किसी व्यक्ति को अपनी पसंद के अस्पताल में भर्ती होने के अधिकार से वंचित किया जा सकता है।

सक्षम भारत की वेबसाईड से जुड़ने के लिए दिए गए QR कोड को स्कैन करे।